



सा./No.: 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 21.09.2017

प्रेषक / From: संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय / कॉम्प्लेक्स /केन्द्रों /एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts. /Hqrs. /Complex /Centres /Units.

महोदय/Sir/ महोदया / Madam

मुझे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित संकल्प एवं कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

I am directed to forward herewith the following Resolution and Office memoranda issued by the Government of India, Ministry of Finance for your information, guidance and compliance.

क्र.स. Sl.No	संदर्भ / Reference	दिनांक /Dated	विषय / Subject
1.	Resolution No.11-1/2016-IC.	06.07.2017	The Recommendations of the 7 th Central Pay Commission on allowances.
2.	OM No.1/2/2016 -E-III(A)	26.07.2017	Revision of rates of Allowances - extension of Government decisions on the recommendations the 7 th CPC in respect of employees of Quasi-Government Organizations, Autonomous Organizations, statutory bodies set-up by and funded / controlled by Central Govt.
3.	OM No.2/5 /2017-E.II(B)	07.07.2017	Implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees.
4.	OM No.12(4) /2016-EIII.A	07.07.2017	Discontinuance of Family Planning Allowance for adoption of small family norms - recommendation of the 7 th Central Pay Commission.
5.	OM No.21/5 /2017-E.II(B)	07.07.2017	Implementation of the recommendations of the 7 th Central Pay Commission relating to grant of Transport Allowance to Central Government employees.
6.	OM No. 29 /1 /2017- E.II(B)	11.07.2017	Payment on account of discontinued allowances – regarding.
7.	OM No.4/1/ 2017 -E.II(B)	13.07.2017	Abolition of Special Compensatory (Hill Area) Allowance – Recommendations of the 7 th Central Pay Commission.
8.	OM No.19030 /1 /2017-E.IV	13.07.2017	Travelling Allowance Rules – Implementation of the 7 th Central Pay Commission.
9.	OM No.11/1 /2017 - E.II(B)	18.07.2017	Special Duty Allowance serving in North Eastern Region & Ladakh - Implementation of 7 th CPC recommendations.
10.	No.28/1/2017-E.II(B)	19.07.2017	Implementation of 7 th CPC recommendations on Allowances - Additional HRA for employees posted in North - East Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and Ladakh.
11.	F.No.19039/03/2017-E.IV	19.07.2017	Implementation of 7 th CPC recommendations on Allowances - Conveyance Allowance
12.	No.3/1/2017-E.II(B)	19.07.2017	Implementation of 7 th CPC recommendations on Allowances - Special Compensatory Allowances subsumed under Tough Location Allowance-I,II& III.

भवदीय/Yours faithfully

(विनोद कुमार)

(विनोद कुमार / Vinod Kumar)

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US (Policy Division)

संलग्न/Encl. :यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) Head, IT Division - with the request to make this letter along with enclosures available on the CSIR website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303

Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939

No. 169]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

सं.11-1/2016-आईसी.—भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III(ए) द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। 08 सितम्बर, 2015 के संकल्प संख्या-1/1/2013-ई.III(ए) के माध्यम से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दी गयी थी। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने तारीख 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट उसके निर्देश निबंधन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की थी।

2. सरकार ने तारीख 25 जुलाई, 2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के पैरा 7 द्वारा भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) को, भत्ते संबंधी समिति को निर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया था। उसने यह भी विनिश्चय किया था कि समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम विनिश्चय किए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर ऐसे किया जाता रहेगा मानो 1 जनवरी, 2016 से वेतन पुनरीक्षित ही न किया गया हो।

3. उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल, 2017 को प्रस्तुत की। सरकार ने विचार करने के पश्चात्, भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें परिशिष्ट I में यथा-विनिर्दिष्ट 34 उपांतरणों के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय किया है। भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के विनिश्चय को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

4. भारतीय नौसेना को दिए गए कुछ भत्तों, जिनका भुगतान इस समय भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाता है, का उल्लेख सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे भत्तों का, जो भारतीय नौसेना के लिए अनुज्ञेय हैं, भुगतान भारतीय नौसेना के अनुरूप भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाएगा।

5. रेल मंत्रालय से संबंधित 12 चालन भत्तों के संबंध में दरें, रेल मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।

6. भत्तों की पुनरीक्षित दरें 01 जुलाई, 2017 से अनुज्ञेय हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

परिशेष I

भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित उपांतरणों के साथ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत भत्तों की सूची

(1)	(2)	(3)	(4)									
क्र. सं.	भत्ते का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार द्वारा स्वीकृत उपांतरण									
1.	अंटार्कटिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा।	जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमशः ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹1500 प्रति दिन और ₹1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गई। दल के नेता को गर्मियों और सर्दियों में क्रमशः ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी।									
2.	ब्रेकडाउन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 – ₹675 प्रति माह की गई।									
3.	रोकड़ संभाल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं: <div>(₹ प्रति माह)</div> <table><tr><th>संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि</th><th>छूटे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें</th><th>संशोधित दरें</th></tr><tr><td><= 5 लाख</td><td>230 - 600</td><td>700</td></tr><tr><td>5 लाख से अधिक</td><td>750 - 900</td><td>1000</td></tr></table>	संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि	छूटे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें	<= 5 लाख	230 - 600	700	5 लाख से अधिक	750 - 900	1000
संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि	छूटे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें										
<= 5 लाख	230 - 600	700										
5 लाख से अधिक	750 - 900	1000										
4.	कोयला पायलट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹45 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गई।									
5.	साईकिल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹180 प्रति माह की गई। व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाए जहां किसी विशेष वर्ग के स्टाफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो।									

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। सभी प्रावधान रेल कार्मिकों पर भी लागू होंगे।	लेवल-12 – 13 के लिए यात्रा प्रभार '50 किमी तक गैर-एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' और लेवल 14 और ऊपर के लिए '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके 'सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार' किया गया। रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
7.	नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए)	बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनाए रखी जाए।	₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹1000 प्रति माह की गई।
8.	नियत मौद्रिक प्रतिपूर्ति	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त पद भत्ता' लागू होगा।	मिलाया न जाएगा और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से ₹54 की गई।
9.	अंत्येष्टि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	नाम में बदलाव के साथ 'अंत्येष्टि व्यय' के रूप में बरकरार रखा जाना है। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹6000 से संशोधित करके ₹9000 की गई।
10.	अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर "राष्ट्रीय अवकाश भत्ता" लागू होगा।	मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। आसूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
11.	अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता	बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य हैं कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परम्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं।	मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹4100 और लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹5300) के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता मिलता रहेगा।
12.	मकान किराया भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं: (i) मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 30%, वाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 20% और जेड श्रेणी (5 लाख से कम

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>आबादी) के शहर के लिए 10% की दर से क्रमशः ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ii) महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का क्रमशः 27%, 18% और 9% तथा महंगाई भत्ते के 50% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।</p>
13.	किट रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एसपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया।
14.	प्रक्षेपण अभियान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा जाए। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
15.	नर्सिंग भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।	विद्यमान दरों को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹4800 प्रति माह से संशोधित करके ₹7200 प्रति माह की गई।
16.	ऑपरेशन थिएटर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹360 प्रति माह से संशोधित करके ₹540 प्रति माह की गई।
17.	समयोपरि भत्ता	सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामले को छोड़कर शेष के लिए समाप्त कर दिया जाए।	मंत्रालयों/विभागों को 'प्रचालन स्टॉफ' की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है। समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।
18.	प्रफेशनल अपडेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक बढ़ाया जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए।	परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाए। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
19.	अर्हता अनुदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नव-प्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं कि: (i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और (ii) बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों को सहयोजित करके पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 तक की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	राशन मनी भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए निःशुल्क राशन और राशन मनी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।	शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए निःशुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
21.	जोखिम भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹60 प्रति माह से संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गईं।
22.	सियाचिन भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाए।	दरें इस प्रकार संशोधित की गईं: लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 से संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹21000 से संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
23.	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
24.	विशेष नियुक्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त कार्य भत्ता' लागू होगा। विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाए।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र सूची में सहायक सब इंस्पेक्टर (आरएम), सहायक सब इंस्पेक्टर (आरओ) और सब इंस्पेक्टर (आरएम) को शामिल किया गया।
25.	विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भत्ता-I, II या III लागू होगा। विशेष झूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष झूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष झूटी भत्ते के साथ छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधन-पूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ते का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
26.	विशेष झूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। विशेष झूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरवरी, 2009 के का. जा. सं. 14017/4/2005-एआईएस (II) के अनुसार 'अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' 25% की दर से दिया जाता है। विशेष झूटी भत्ता 12.5% की दर से दिया जाता है। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। इन दोनों भत्तों अर्थात् 'अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' और 'विशेष झूटी भत्ता' का वर्तमान की तरह क्रमशः 20% और 10% की संशोधित दरों से भुगतान जारी रहेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	विशेष घटना/जांच/ सुरक्षा भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय में मामला पेश किया जाए।	विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल झूटी के लिए मूल वेतन के 40% से संशोधित करके 55% और गैर ऑपरेशनल झूटी के लिए मूल वेतन के 20% से संशोधित करके 27.5% किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के 20% की दर से प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के प्रस्ताव की जांच करेगा।
28.	विशेष चालन स्टॉफ भत्ता	बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए।	इस भत्ते का नाम 'अतिरिक्त भत्ता' बना रहेगा।
29.	तकनीकी भत्ता	तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	₹3000 प्रति माह और ₹4500 प्रति माह की दर से तकनीकी भत्ते (स्तर – I और II) की विद्यमान प्रणाली 31.03.2018 तक जारी रखी जाए। बदलती रक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों, बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों को सहयोजित करके अर्हता अनुदान (रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन) के साथ-साथ तकनीकी भत्ते (स्तर-I और II) के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 से पहले पूरी की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा के बाद ही तकनीकी भत्ते (स्तर-II) को 31.03.2018 से आगे जारी रखा जाए।
30.	प्रशिक्षण भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए। यह भत्ता पात्र कर्मचारी को उसके संपूर्ण करियर के दौरान अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा।	5 वर्ष की अधिकतम सीमा को हटाया जाएगा। कार्यकालों के बीच मानक उपशमन अवधि लागू होगी।
31.	यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 से 8 हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे। यात्रा पात्रताओं के लिए रक्षा बलों के लेवल 5 को लेवल 6 में मिला दिया जाएगा। विद्यमान प्रणाली को रेल मंत्रालय में जारी रखा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)									
32.	कोषागार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	<p>रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं:</p> <p style="text-align: right;">(₹ प्रति माह)</p> <table><tr><td>संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि</td><td>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें</td><td>संशोधित दरें</td></tr><tr><td><= 5 लाख</td><td>230 - 600</td><td>700</td></tr><tr><td>5 लाख से अधिक</td><td>750 - 900</td><td>1000</td></tr></table>	संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें	<= 5 लाख	230 - 600	700	5 लाख से अधिक	750 - 900	1000
संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें										
<= 5 लाख	230 - 600	700										
5 लाख से अधिक	750 - 900	1000										
33.	वर्दी भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका वार्षिक भुगतान किया जाए।	<p>सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत की गईं:</p> <p>निम्नलिखित वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें:</p> <p>(i) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) कार्मिक – ऑपरेशनल और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमशः ₹27,800 प्रतिवर्ष और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(ii) नर्स – ₹1800 प्रतिमाह की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।</p> <p>आब्रजन ब्यूरो की सभी जांच चौकियों पर भी लागू किया जाए।</p>									
34.	धुलाई भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	<p>नर्सों के संबंध में परिधान भत्ते में मिला दिया गया और नर्सों के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया।</p>									

परिशिष्ट II

भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)
क्र.सं.	भत्ते का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1	दुर्घटना भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
2	कार्यकरण भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त पद भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
3	वैमानिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
4	एअर डिस्पेच वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
5	एअर स्टूअर्ड भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
6	उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
7	किलोमीटर के बदले भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।



(1)	(2)	(3)	(4)
8	रनिंग रूम सुविधाओं के बदले भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
9	वार्षिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
10	अंटार्कटिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा।	जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमशः ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹1500 प्रति दिन और ₹1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गई। दल के नेता को गर्मियों और सर्दियों में क्रमशः ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी।
11	सहायक रोकड़िया भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
12	एएसवी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
13	प्रतिकूल जलवायु भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-II में मिला दिया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
14	भूटान प्रतिपूरक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
15	बायलर वॉच कीपिंग भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया गया। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
16	पुस्तक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
17	विश्राम भंग भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
18	ब्रेकडाउन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 – ₹675 प्रति माह की गई।
19	ब्रीफकेस भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
20	शिविर भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित प्रादेशिक सेना भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
21	कैटीन भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)												
22	देखभाल भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत												
23	रोकड़ संभाल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	<p>रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं:</p> <p style="text-align: right;">(₹ प्रति माह)</p> <table border="1"> <tr> <td>संभाली रोकड़ मासिक राशि</td><td>गए की औसत</td><td>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें</td><td>संशोधित दरें</td></tr> <tr> <td><= 5 लाख</td><td></td><td>230 - 600</td><td>700</td></tr> <tr> <td>5 लाख से अधिक</td><td></td><td>750 - 900</td><td>1000</td></tr> </table>	संभाली रोकड़ मासिक राशि	गए की औसत	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें	<= 5 लाख		230 - 600	700	5 लाख से अधिक		750 - 900	1000
संभाली रोकड़ मासिक राशि	गए की औसत	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें												
<= 5 लाख		230 - 600	700												
5 लाख से अधिक		750 - 900	1000												
24	बाल शिक्षा भत्ता	बरकरार रखा जाए। भुगतान प्रक्रिया सरल बनाई जाए।	स्वीकृत												
25	विद्रोह प्रतिरोध भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत												
26	वर्गीकरण भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत												
27	वस्त्र भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल कर दिया जाए।	स्वीकृत												
28	कोयला पायलट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	<p>बरकरार रखा गया।</p> <p>विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया।</p> <p>दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹45 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गई।</p>												
29	'कोबरा' भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए	स्वीकृत												
30	कमान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत												
31	कमांडो भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत												
32	वाणिज्य भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत												
33	क्वार्टर के बदले प्रतिपूर्ति	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास" हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू किए जाएं।	स्वीकृत												
34	प्रतिपूरक (निर्माण अथवा सर्वेक्षण) भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत												

(1)	(2)	(3)	(4)
35	मिश्रित वैयक्तिक साज-संभाल भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। 50% की वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
36	कॉडीमेंट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
37	निरंतर उपस्थिति भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
38	वाहन भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
39	कुकिंग अलाउंस	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
40	जीवन यापन भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
41	न्यायालय भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
42	साईकिल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹180 प्रति माह की गई। व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाएगा जहां किसी विशेष वर्ग के स्टॉफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो।
43	दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। सभी प्रावधान रेल कार्मिकों पर भी लागू होंगे।	लेवल-12 – 13 के लिए यात्रा प्रभार '50 किमी तक गैर-एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' और लेवल 14 और ऊपर के लिए '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके 'सरकारी कार्य के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार' किया गया। रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
44	विदेश यात्रा पर दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
45	महंगाई भत्ता (डीए)	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	यह समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं था।
46	सिविल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता	बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 गुणे की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
47	रक्षा कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता	बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 गुणे की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
48	डेस्क भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
49	वियोजन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
50	आहार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
51	गोताखोरी भत्ता, डिप मनी और परिचर भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
52	दोहरा प्रभार भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त पद भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
53	शैक्षिक रियायत	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
54	बिजली भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
55	मंत्रिमंडल सचिव के लिए सत्कार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
56	भारतीय रेलवे में सत्कार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
57	अतिरिक्त छूटी भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू होगा।	स्वीकृत
58	परिवार आवास भत्ता (एफएए)	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर "अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास" हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू होंगे।	स्वीकृत
59	परिवार मकान किराया भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
60	परिवार नियोजन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
61	फील्ड एरिया भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
62	नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए)	बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनायी रखी जाए।	₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹1000 प्रति माह की गई।
63	नियत मौद्रिक प्रतिपूर्ति	इसे एक पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त पद भत्ता' लागू होगा।	मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से बढ़ाकर ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से बढ़ाकर ₹54 की गई।
64	फ्लैग स्टेशन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू होगा।	स्वीकृत
65	उड़ान प्रभार प्रमाणपत्र भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू होगा।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
66	उड़ान भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
67	उड़ान दस्ता भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
68	फ्री फॉल जम्प इन्स्ट्रक्टर भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
69	अंत्येष्टि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	नाम में बदलाव के साथ 'अंत्येष्टि व्यय' के रूप में बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹6000 से संशोधित करके ₹9000 की गई।
70	घाट भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
71	अच्छी सेवा/अच्छा आचरण/बैज वेतन	बरकरार रखा जाए। इसमें 2.25 के गुणांक से वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
72	केश कर्तन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे "मिश्रित व्यक्तिगत साज-संभाल भत्ते" में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
73	अक्षमता भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
74	दुष्कर क्षेत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 के गुणांक से युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
75	हार्डलाइंग मनी अलाउंस	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। पूर्ण दर का भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए	स्वीकृत
76	मुख्यालय भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
77	स्वास्थ्य एवं मलेरिया भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
78	उच्च स्थान भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
79	उच्चतर दक्षता भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए भाषा पुरस्कार अथवा सिविल कार्मिकों हेतु उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा।	स्वीकृत
80	सिविल कार्मिकों हेतु उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
81	अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता लागू होगा।	मिलाया न गया और पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। आसूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
82	अवकाश आर्थिक प्रतिपूर्ति	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
83	अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता	बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य हैं कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परम्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं।	मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹4100 और लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹5300) के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/ रोगी देखभाल भत्ता मिलता रहेगा।
84	मकान किराया भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं: (i) मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 30%, वाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 20% और जेड श्रेणी (5 लाख से कम आबादी) के शहर के लिए 10% की दर से क्रमशः ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। (ii) महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का क्रमशः 27%, 18% और 9% तथा महंगाई भत्ते के 50% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।
85	कुटीर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
86	जल सर्वेक्षण भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
87	प्रारंभिक उपकरण भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
88	अनुदेश भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "प्रशिक्षण भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
89	इंटरनेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
90	अन्वेषण भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
91	द्वीप समूह विशेष ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
92	जज महाधिवक्ता विभागीय परीक्षा अवार्ड	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "रक्षा कार्मिकों हेतु उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन" लागू किया जाए।	स्वीकृत
93	किलोमीटररेज भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
94	किट रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एसपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया।
95	भाषा भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
96	भाषा अवार्ड	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
97	भाषा ईनाम एवं भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
98	प्रक्षेपण अभियान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
99	सावकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया जाए। यथोचित परिवर्तन करके एक अतिरिक्त निःशुल्क रेलवे वारंट केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सभी कार्मिकों को दिया जाए।	सावकाश यात्रा रियायत के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें बगैर किसी परिवर्तन के स्वीकार की जाती हैं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय नौसेना के कार्मिक फील्ड ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किए जाते हैं, इसलिए अतिरिक्त निःशुल्क रेलवे वारंट भारतीय तटरक्षक बल को नहीं दिया जाएगा।
100	पुस्तकालय भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
101	मारकोस एंड चेरियट अलाउंस	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
102	पदक भत्ता	बरकरार रखा जाए।	स्वीकृत
103	मेस भत्ता	"भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण" के अधीन "चल स्टॉफ" के लिए बरकरार रखा जाए और 50% की वृद्धि की जाए। नर्सिंग स्टॉफ के लिए इसे समाप्त किया जाए।	स्वीकृत
104	महानगर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
105	सड़क से यात्रा के लिए मील भत्ता	बरकरार रखा जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
106	मोबाइल फोन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
107	शौर्य पुरस्कारों से संबंधित मौद्रिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
108	राष्ट्रीय अवकाश भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
109	समाचार पत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
110	रात्रि झूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
111	रात्रि गश्त भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
112	प्रेक्टिसबंदी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
113	परमाणु अनुसंधान संयंत्र सहायता भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
114	नर्सिंग भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।	विद्यमान दरों को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹4800 प्रति माह से संशोधित करके ₹7200 प्रति माह की गई।
115	रक्षा बलों में सरकारी आतिथ्य अनुदान	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
116	स्थानापन्न भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
117	ऑपरेशन थिएटर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹360 प्रति माह से संशोधित करके ₹540 प्रति माह की गई।
118	अर्दली भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
119	संगठन विशेष वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
120	फुटकर खर्च भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "विदेश यात्रा पर दैनिक भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
121	पोशाक भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
122	आउट स्टेशन (संरोध) भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।

(1)	(2)	(3)	(4)
123	आउट स्टेशन (रिलीविंग) भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिमूचित की जाएंगी।
124	आउट-टर्न भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
125	समयोपरि भत्ता	सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर समाप्त कर दिया जाए।	मंत्रालयों/विभागों को 'प्रचालन स्टॉफ' की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है। समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।
126	पैरा भत्ते	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
127	पैरा-जम्प अनुदेशक भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
128	संसद सहायक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
129	पीसीओ भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
130	स्नातकोत्तर भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
131	प्रफेशनल अपडेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% बढ़ाया जाए। कुछ और वर्गों पर भी लागू किया जाए।	परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाएगा। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
132	परियोजना भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
133	अर्हता भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
134	अर्हता अनुदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नव-प्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं कि: (i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और (ii) पाठ्यक्रमों की समीक्षा बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों को सहयोजित करके 31.12.2017 तक कर ली जाए।
135	अर्हता वेतन	बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 से गुणा करके बढ़ाया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
136	राजभाषा भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
137	राजधानी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
138	राशन मनी भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए निःशुल्क राशन और राशन मनी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।	शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए निःशुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
139	जलपान भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 के गुणांक में बढ़ाया जाए।	स्वीकृत
140	किराया मुक्त आवास	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
141	सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार	बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 के गुणांक में बढ़ाया जाए।	स्वीकृत
142	जोखिम भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹60 प्रति माह से संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गईं।
143	पोशाक भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
144	पोशाक रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
145	बचत बैंक भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
146	सागर गमन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
147	गुप्त भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
148	जूता भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
149	आशुलिपि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
150	शंटिंग भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।



(1)	(2)	(3)	(4)
151	सियाचिन भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाए।	दरें इस प्रकार संशोधित की गईं: लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 से संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹21000 से संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
152	क्वार्टर के बदले एकल भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास" हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू किए जाएं।	स्वीकृत
153	प्रसाधन साबुन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे मिश्रित वैयक्तिक साज-संभाल भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
154	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
155	निःशक्त महिलाओं के लिए बाल देखभाल हेतु विशेष भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसमें 100% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
156	मुख्य सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा अधिकारियों को विशेष भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
157	विशेष नियुक्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त कार्य भत्ता' लागू होगा। विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाए।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र सूची में एसआई (आरएम), एसआई (आरओ) और एसआई (आरएम) को शामिल किया गया।
158	विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
159	विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भत्ता-I, II या III लागू होगा। विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधन-पूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
160	विशेष डीओटी वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
161	विशेष ड्यूटी भत्ता	<p>बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।</p> <p>विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए।</p>	<p>कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरवरी, 2009 के का. जा. सं. 14017/4/2005-एआईएस (II) के अनुसार 'अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' 25% की दर से दिया जाता है।</p> <p>विशेष ड्यूटी भत्ता 12.5% की दर से दिया जाता है।</p> <p>0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।</p> <p>इन दोनों भत्तों अर्थात् 'अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' और 'विशेष ड्यूटी भत्ता' का भुगतान वर्तमान की तरह क्रमशः 20% और 10% की संशोधित दरों से जारी रहेगा।</p>
162	विशेष बल भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
163	विशेष घटना/जांच/सुरक्षा भत्ता	<p>बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।</p> <p>राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करे और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत करे।</p>	<p>विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के 40% से संशोधित करके 55% और गैर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के लिए 20% से संशोधित करके 27.5% किया गया।</p> <p>राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के 20% की दर से प्रदान किया जाएगा।</p> <p>यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के प्रस्ताव की जांच करेगा।</p>
164	विशेष एलसी गेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
165	विशेष एनसीआरबी वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
166	विशेष चालन स्टॉफ भत्ता	बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्गों पर भी लागू किया जाए।	भत्ते का नाम 'अतिरिक्त भत्ता' बना रहेगा।
167	विशेष वैज्ञानिक वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
168	विशेषज्ञ भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
169	चश्मा भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
170	विभाजित ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
171	अध्ययन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
172	पनडुब्बी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
173	पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच1 के अनुसार यथानुपात आधार पर किया जाए।	स्वीकृत
174	पनडुब्बी तकनीकी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
175	निर्वाह भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
176	प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में सत्कार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
177	सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारियों को सत्कार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
178	सुंदरबन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में शामिल किया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
179	प्रादेशिक सेना अधिदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित प्रादेशिक सेना भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
180	सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
181	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)									
182	तकनीकी भत्ता	तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	₹3000 प्रति माह और ₹4500 प्रति माह की दर से तकनीकी भत्ते (स्तर - I और II) की विद्यमान प्रणाली 31.03.2018 तक जारी रखी जाए। बदलती रक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों, बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों को सहयोजित करके अर्हता अनुदान (रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन) के साथ-साथ तकनीकी भत्ते (स्तर-I और II) के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 से पहले पूरी की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा के बाद ही तकनीकी भत्ते (स्तर-II) को 31.03.2018 से आगे जारी रखा जाए।									
183	कार्यकाल भत्ता	बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 के गुणांक से वृद्धि की जाए।	स्वीकृत									
184	परीक्षण पायलट और उड़ान परीक्षण अभियंता भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत									
185	प्रशिक्षण भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। यह भत्ता पात्र कर्मचारी के लिए उसके संपूर्ण करियर के दौरान पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ही देय होगा।	पांच वर्ष की निर्धारित सीमा को हटाया गया। कार्यकालों के बीच मानक उपशमन अवधि लागू होगी।									
186	प्रशिक्षण वजीफा	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत									
187	परिवहन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत									
188	यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 से 8 हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे। यात्रा पात्रताओं के लिए रक्षा बलों के लेवल 5क को लेवल 6 में मिला दिया गया। विद्यमान प्रणाली को रेल मंत्रालय में जारी रखा जाएगा।									
189	कोषागार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	रोकड़ संभाल भत्ते और कोषागार भत्ते को परस्पर पर मिला दिया गया और दरों को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया: <div>(₹ प्रतिमाह)</div> <table><tr><td>संभाली गई औसत मासिक रोकड़</td><td>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार दरें</td><td>संशोधित दरें</td></tr><tr><td><= 5 लाख</td><td>230-600</td><td>700</td></tr><tr><td>5 लाख से अधिक</td><td>750-900</td><td>1000</td></tr></table>	संभाली गई औसत मासिक रोकड़	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार दरें	संशोधित दरें	<= 5 लाख	230-600	700	5 लाख से अधिक	750-900	1000
संभाली गई औसत मासिक रोकड़	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार दरें	संशोधित दरें										
<= 5 लाख	230-600	700										
5 लाख से अधिक	750-900	1000										
190	जनजातीय क्षेत्र भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में शामिल कर दिया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत									

(1)	(2)	(3)	(4)
191	भ्रमण भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
192	वर्दी भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत की गई हैं: निम्नलिखित श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न दरें: (i) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) कार्मिक - इन्हें ऑपरेशनल और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमशः ₹27,800 और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जाएगा। (ii) नर्स - इन्हें ₹1800 प्रतिमाह की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा। आब्रजन ब्यूरो की सभी जांच चौकियों पर लागू किया जाए।
193	इकाई प्रमाण पत्र एवं प्रभार प्रमाण पत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
194	सतर्कता भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
195	प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
196	धुलाई भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	नर्सों के संबंध में परिधान भत्ते में शामिल किया गया और नर्सों के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया।
197	रेलवे के लिए नए भत्ते: (i) विशेष ट्रेन कंट्रोलर का भत्ता, और (ii) ट्रैक मेंटेनरों के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ता अग्निशमन स्टाफ के लिए नया भत्ता: (i) केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अग्निशमन स्टाफ के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ता	(i) विशेष ट्रेन कंट्रोलर भत्ता - सेक्शन कंट्रोलर और उप मुख्य कंट्रोलर को ₹5,000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। (ii) भारतीय रेल के ट्रैक मेंटेनर-I, II, III और IV को जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार जोखिम एवं कठिनाई भत्ता दिया जाए (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹2700 और लेवल 9 और उससे उपर के लिए ₹3400)। अग्निशमन स्टाफ के लिए नया भत्ता: (i) जोखिम एवं कठिनाई भत्ता मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच3 (लेवल 8 और उससे नीचे के लेवल के लिए ₹2700 और लेवल 9 तथा उससे ऊपर के लेवल के लिए ₹3400) के अनुसार जोखिम एवं कठिनाई भत्ता।	स्वीकृत

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
RESOLUTION

New Delhi, the 6th July, 2017

No. 11-1/2016-IC.—The Seventh Central Pay Commission (the Commission) was set up by the Government of India vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the 28th February, 2014. The period for submission of report by the Commission was extended upto 31st December, 2015 vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the 8th September, 2015. The Commission, on 19th November, 2015, submitted its Report on the matters covered in its Terms of Reference as specified in the aforesaid Resolution dated the 28th February, 2014.

2. The Government, vide Para 7 of the Resolution No. 1-2/2016- IC, dated 25th July, 2016, decided to refer the allowances (except Dearness Allowance) to the Committee on Allowances (the Committee). It was also decided that till a final decision on allowances is taken based on the recommendations of the Committee, all allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from 1st day of January, 2016.

3. The said Committee submitted its Report on 27th April, 2017. The Government, after consideration, has decided to accept the recommendations of the Commission on allowances with 34 modifications as specified in **Appendix I**. The Statement showing the recommendations of the Commission on allowances and the Government's decision thereon is annexed at **Appendix II**.

4. Some of the allowances paid to the Indian Navy which are also paid to the Indian Coast Guard at present have not been mentioned in the Report of the Commission. The Government has decided that these allowances which are admissible to the Indian Navy shall also be paid to the Indian Coast Guard at par with the Indian Navy.

5. The rates in respect of 12 running allowances relating to the Ministry of Railways shall be notified by the Ministry of Railways with the concurrence of the Ministry of Finance.

6. The revised rates of allowances shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Ministries and/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union territories and all other concerned.

R. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Appendix I

List of allowances recommended by the Seventh Central Pay Commission (7th CPC) along with modifications as approved by the Government of India

(1)	(2)	(3)	(4)
S. No.	Name of the Allowance	Recommendations of the 7 th CPC	Modifications accepted by the Government
1.	Antarctica Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix	To be kept out of Risk and Hardship Matrix and to be paid on per day basis. Rates revised from ₹1125 per day to ₹1500 per day and from ₹1688 per day to ₹2000 per day in Summer and Winter respectively. Team Leader to get 10% extra @₹1650 per day and ₹2200 per day in Summer and Winter respectively

(1)	(2)	(3)	(4)									
2.	Breakdown Allowance	Abolished	Retained. Existing Rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹120 – ₹300 per month to ₹270 – ₹675 per month									
3.	Cash Handling Allowance	Abolished	Subsumed in Cash Handling and Treasury Allowance and rates revised as under: (in ₹, per month) <table><tr><th>Amount of average monthly cash handled</th><th>Sixth Central Pay Commission rates (6th CPC)</th><th>Revised Rates</th></tr><tr><td><= 5 lakh</td><td>230-600</td><td>700</td></tr><tr><td>Over 5 lakh</td><td>750-900</td><td>1000</td></tr></table>	Amount of average monthly cash handled	Sixth Central Pay Commission rates (6 th CPC)	Revised Rates	<= 5 lakh	230-600	700	Over 5 lakh	750-900	1000
Amount of average monthly cash handled	Sixth Central Pay Commission rates (6 th CPC)	Revised Rates										
<= 5 lakh	230-600	700										
Over 5 lakh	750-900	1000										
4.	Coal Pilot Allowance	Abolished	Retained. Existing rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹45 per trip to ₹102 for first trip and from ₹15 per trip to ₹34 for every subsequent trip.									
5.	Cycle Allowance	Abolished	Retained. Existing rates of ₹90 per month doubled to ₹180 per month for Department of Posts and Railways. To be retained in other Ministries/Departments where there is functional justification for any particular category of staff with the approval of Department of Expenditure.									
6.	Daily Allowance	Retained. Rationalized. All provisions will apply to Railways personnel also.	Travelling Charges for Level -12 – 13 revised from 'Non-AC Taxi charges up to 50 km to 'AC taxi charges upto 50 Kms.' and for level 14 and above to be revised from 'AC Taxi charges up to 50 km' to 'AC taxi charges as per actual expenditure commensurate with official engagements'. Existing system of Daily allowance in the Ministry of Railways to continue.									
7.	Fixed Medical Allowance (FMA)	Retained. Status Quo to be maintained	Existing rate of ₹500 per month revised to ₹1000 per month.									
8.	Fixed Monetary Compensation	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance"	Not to be subsumed and retained as a separate allowance. Existing rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹50 to ₹115 for full beat and from ₹24 to ₹54 for sharing a beat.									

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Funeral Allowance	Abolished	Retained with change in nomenclature as 'Funeral Expense'. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹6000 to ₹9000.
10.	Holiday Allowance Compensatory	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by National Holiday Allowance	Not to be subsumed and retained as a separate allowance. Existing system to continue in Intelligence Bureau (IB) and Research and Analysis Wing (RAW).
11.	Hospital Patient Care Allowance (HPCA)/Patient Care Allowance (PCA)	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix. HPCA and PCA are admissible to ministerial staff as well on the premise that the entire hospital area carries the risk of communicable diseases. This practice should be stopped and HPCA/PCA should be admissible to only those employees who come in continuous and routine contact with the patients.	Ministerial Staff to continue to get HPCA/PCA as per R1H3 (₹4100 for level 8 and below and ₹5300 for level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix
12.	House Rent Allowance (HRA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8	The recommendations of the 7 th CPC is accepted with the following modifications: (ii) HRA shall not be less than ₹5,400 per month, ₹3,600 per month and ₹1,800 per month calculated @30% of minimum pay for X (population of 50 lakh & above), 20% for Y (5 to 50 lakh) and 10% for Z (below 5 lakh) category of cities. (ii) HRA shall be revised to 27%, 18% & 9% of Basic Pay in X, Y & Z cities when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further to 30%, 20% and 10% of Basic Pay in X, Y & Z cities when DA crosses 50%.
13.	Kit Maintenance Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance	Subsumed in Dress Allowance for Special Protection Group (SPG) and factored in for determining the revised rates of Dress Allowance for SPG.
14.	Launch Campaign Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Nursing Allowance	Retained. Rationalized.	Existing rates multiplied by 1.5. Rates revised from ₹4800 per month to ₹7200 per month.
16.	Operation Theatre Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹360 per month to ₹540 per month.
17.	Overtime Allowance (OTA)	Abolished except for operational staff and industrial employees governed by statutory provisions.	Ministries/Departments to prepare a list of those staff coming under the category of 'operational staff'. Rates of Overtime Allowance not to be revised upwards.
18.	Professional Allowance Update	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories	This allowance to continue to be paid to non-gazetted staff of Department of Atomic Energy (DAE). Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
19.	Qualification Grant	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Higher Qualification Incentive for Defence Personnel. Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel	7 th CPC recommendations accepted with the modifications that: (i) This will not include Tier – II courses, and (ii) Courses will be reviewed by associating experts, including outside professionals and academicians by 31.12.2017.
20.	Ration Money Allowance (RMA)	Retained. Rationalized. Provision of free rations and the grant of Ration Money Allowance to officers of Defence forces posted in peace areas should be withdrawn	Provision of free ration for officers of Defence Forces shall be discontinued in peace areas. RMA shall continue to be paid to officers of Defence Forces posted in peace areas. The cash shall be credited directly into the bank accounts of officers.
21.	Risk Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 2.25. Rates revised from ₹60 per month to ₹135 per month.
22.	Siachen Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and	Rates revised from: ₹31500 to ₹42500 per month for Level 9 and above, and

(1)	(2)	(3)	(4)
		below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	₹21000 per month to ₹30000 per month for level 8 and below
23.	Space Technology Allowance	Abolished	Retained. Existing rate to be multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
24.	Special Appointment Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance". Granted to Central Armed Police Force Personnel holding special appointments	To include Assistant Sub Inspector (Radio Mechanic), Assistant Sub Inspector (Radio Operator) and Sub Inspector (Radio Mechanic) in the list eligible for Extra Work Allowance @2% of Basic Pay per month with the conditions recommended by the 7 th CPC.
25.	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Tough Location Allowance (TLA) -I, II or III. Tough Location Allowance will not be admissible along with Special Duty Allowance.	7 th CPC recommendations that Tough Location Allowance (TLA) will not be admissible along with Special Duty Allowance (SDA) accepted subject to condition that employees be given the additional option to avail of the benefit of Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA) at pre-revised rates under the 6 th CPC regime along with SDA at revised rates of 7 th CPC
26.	Special Duty Allowance (SDA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. SDA for All India Service (AIS) officers should be paid at the rate of 30 percent of Basic Pay and for other civilian employees at the rate of 10 percent of Basic Pay.	As per DoPT's OM No. 14017/4/2005-AIS (II) dated 10 th February, 2009, 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of All India Service (AIS) officers' is granted @25%. Special Duty Allowance (SDA) is granted @12.5%. Rationalized by a factor of 0.8. Both these allowances namely 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of AIS' and Special Duty Allowance (SDA) shall continue to be paid separately as at present at the revised rates of 20% and 10% respectively.
27.	Special Incident/Investigation/Security Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Department of Revenue should assess the risk profile of the officials of the Enforcement Directorate (ED) at various levels and thereafter make a case to Ministry of	Special Security Allowance (SSA) for Special Protection Group (SPG) to be revised from 40% to 55% of Basic Pay for operational duties and from 20% to 27.5% of Basic Pay for non – operational duties. National Technical Research Organisation (NTRO) employees to be granted this allowance @20% of Basic Pay.

(1)	(2)	(3)	(4)									
		Finance for grant of Risk and Hardship Allowance, if any, as per appropriate cell.	This allowance was granted to Enforcement Directorate as an ad – hoc measure with the approval of Department of Expenditure pending recommendations of the 7 th CPC. Accordingly, this allowance to be withdrawn from ED with effect from 01.07.2017. As per recommendations of the 7 th CPC, Department of Revenue to examine proposal or Risk & Hardship allowance for ED to make a case to Ministry of Finance for granting Risk and Hardship based allowance to ED officials, if any.									
28.	Special Running Staff Allowance	Retained. Extended to some more categories	Name of the allowance to continue as 'Additional Allowance'.									
29.	Technical Allowance	<p>Tier-I of the Technical Allowance will continue to be paid on a monthly basis.</p> <p>Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel</p>	<p>Existing system of Technical Allowance (Tier – I and II) to continue at ₹3000 per month and ₹4500 per month up to 31.03.2018.</p> <p>Courses of Technical Allowance (Tier –I and II) along with Qualification Grant (Higher Qualification Incentive for Defence Personnel) to be reviewed by associating experts, outside professionals and academicians in order to keep pace with changing defence requirements.</p> <p>Review of Courses to be completed before 31.12.2017.</p> <p>Technical Allowance (Tier – II) to continue beyond 31.03.2018 only after review of courses.</p>									
30.	Training Allowance	<p>Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Extended to some more categories.</p> <p>The allowance will be payable to an eligible employee for a maximum period of five years only during the entire career.</p>	<p>Ceiling of 5 years period to be removed.</p> <p>Standard cooling off period between tenures will apply.</p>									
31.	Travelling Allowance	<p>Retained. Rationalized.</p> <p>Indian Railways to reconsider its position regarding air travel to its employees.</p>	<p>Level 6 to 8 of Pay Matrix to be entitled for Air travel.</p> <p>Level 5 A of Defence Forces to be clubbed with Level 6 for travelling entitlements.</p> <p>Existing system to continue in Ministry of Railways.</p>									
32.	Treasury Allowance	Abolished	<p>Subsumed in Cash Handling and Treasury Allowance and rates revised as under:</p> <p>(in ₹, per month)</p> <table><tr><th>Amount of average monthly cash handled</th><th>6th CPC Rates</th><th>Revised Rates</th></tr><tr><td><= 5 lakh</td><td>230-600</td><td>700</td></tr><tr><td>Over 5 lakh</td><td>750-900</td><td>1000</td></tr></table>	Amount of average monthly cash handled	6 th CPC Rates	Revised Rates	<= 5 lakh	230-600	700	Over 5 lakh	750-900	1000
Amount of average monthly cash handled	6 th CPC Rates	Revised Rates										
<= 5 lakh	230-600	700										
Over 5 lakh	750-900	1000										

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Uniform Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance and to be paid annually.	7 th CPC recommendations accepted with following modifications: Different rates for the following categories: (i) Special Protection Group (SPG) personnel- to be paid annually @ ₹27,800 per annum and ₹21,225 per annum for operational and non – operational duties respectively. (ii) Nurses – to be paid monthly @ ₹1800 per month To be extended to all Check Points of Bureau of Immigration.
34.	Washing Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance	Subsumed in Dress Allowance in respect of Nurses and factored in for determining the revised rates of Dress Allowance for Nurses.

Appendix II

Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on Allowances and the Government's decision thereon

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No.	Name of the Allowance	Recommendations of 7 th CPC	Decision of the Government
1	Accident Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
2	Acting Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance."	Accepted
3	Aeronautical Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
4	Air Despatch Pay	Abolished.	Accepted
5	Air Steward Allowance	Abolished.	Accepted
6	Air Worthiness Certificate Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
7	Allowance in Lieu of Kilometrage (ALK)	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
8	Allowance in Lieu of Running Room Facilities	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Annual Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories.	Accepted
10	Antarctica Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix	To be kept out of Risk and Hardship Matrix and to be paid on per day basis. Rates revised from ₹1125 per day to ₹1500 per day and from ₹1688 per day to ₹2000 per day in Summer and Winter respectively. Team Leader to get 10% extra @₹1650 per day and ₹2200 per day in Summer and Winter respectively
11	Assisting Cashier Allowance	Abolished.	Accepted
12	Accounts Stock Verifiers (ASV) Allowance	Abolished.	Accepted
13	Bad Climate Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Tough Location Allowance-III. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
14	Bhutan Compensatory Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
15	Boiler Watch Keeping Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
16	Book Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
17	Breach of Rest Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
18	Breakdown Allowance	Abolished	Retained. Existing Rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹120 – ₹300 per month to ₹270 – ₹675 per month
19	Briefcase Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
20	Camp Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Territorial Army Allowance.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)									
21	Canteen Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted									
22	Caretaking Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance"	Accepted									
23	Cash Handling Allowance	Abolished	Subsumed in Cash Handling and Treasury Allowance and rates revised as under: <div>(in ₹, per month)</div> <table><tr><th>Amount of average monthly cash handled</th><th>6th CPC rates</th><th>Revised Rates</th></tr><tr><td><= 5 lakh</td><td>230-600</td><td>700</td></tr><tr><td>Over 5 lakh</td><td>750-900</td><td>1000</td></tr></table>	Amount of average monthly cash handled	6 th CPC rates	Revised Rates	<= 5 lakh	230-600	700	Over 5 lakh	750-900	1000
Amount of average monthly cash handled	6 th CPC rates	Revised Rates										
<= 5 lakh	230-600	700										
Over 5 lakh	750-900	1000										
24	Children Education Allowance (CEA)	Retained. Procedure of payment simplified.	Accepted.									
25	CI Ops Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted									
26	Classification Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted									
27	Clothing Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted.									
28	Coal Pilot Allowance	Abolished	Retained. Existing rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹45 per trip to ₹102 for first trip and from ₹15 per trip to ₹34 for every subsequent trip.									
29	Command Battalion for Resolute Action (COBRA) Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted									
30	Command Allowance	Abolished	Accepted									
31	Commando Allowance	Abolished	Accepted									
32	Commercial Allowance	Abolished	Accepted									

(1)	(2)	(3)	(4)
33	Compensation in Lieu of Quarters (CILQ)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed provisions for Housing for Persons Below Officers Rank (PBORs).	Accepted
34	Compensatory (Construction or Survey) Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
35	Composite Personal Maintenance Allowance (CPMA)	Retained. Rationalised. Enhanced by 50%. Extended to some more categories.	Accepted
36	Condiment Allowance	Abolished.	Accepted
37	Constant Attendance Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
38	Conveyance Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
39	Cooking Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
40	Cost of Living Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
41	Court Allowance	Abolished.	Accepted
42	Cycle Allowance	Abolished	Retained. Existing rates of ₹90 per month doubled to ₹180 per month for Department of Posts and Railways. To be retained in other Ministries/Departments where there is functional justification for any particular category of staff with the approval of Department of Expenditure.

(1)	(2)	(3)	(4)
43	Daily Allowance	Retained. Rationalized. All provisions will apply to Railways personnel also.	Travelling Charges for Level -12 – 13 revised from 'Non-AC Taxi charges up to 50 km to 'AC taxi charges upto 50 Kms.' and for level 14 and above to be revised from 'AC Taxi charges up to 50 km' to 'AC taxi charges as per actual expenditure commensurate with official engagements'. Existing system of Daily allowance in the Ministry of Railways to continue.
44	Daily Allowance on Foreign Travel	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
45	Dearness Allowance (DA)	Retained. Status Quo to be maintained.	Not within the purview of the Committee.
46	Deputation (Duty) Allowance for Civilians	Retained. Ceilings enhanced by 2.25.	Accepted
47	Deputation (Duty) Allowance for Defence Personnel	Retained. Ceilings enhanced by 2.25.	Accepted
48	Desk Allowance	Abolished.	Accepted
49	Detachment Allowance	Retained. Rationalized. Enhanced by 50%.	Accepted
50	Diet Allowance	Abolished.	Accepted
51	Diving Allowance, Dip Money and Attendant Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
52	Dual Charge Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance".	Accepted
53	Educational Concession	Retained. Rationalized. Extended to some more categories.	Accepted
54	Electricity Allowance	Abolished.	Accepted
55	Entertainment Allowance for Cabinet Secretary	Abolished.	Accepted
56	Entertainment Allowance in Indian Railways	Abolished.	Accepted
57	Extra Duty Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
58	Family Accommodation Allowance (FAA)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed provisions for Housing for PBORs.	Accepted
59	Family HRA Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
60	Family Planning Allowance	Abolished.	Accepted
61	Field Area Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
62	Fixed Medical Allowance (FMA)	Retained. Status Quo to be maintained.	Existing rate of ₹500 per month revised to ₹1000 per month.
63	Fixed Monetary Compensation	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance"	Not to be subsumed and retained as a separate allowance. Existing rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹50 to ₹115 for full beat and from ₹24 to ₹54 for sharing a beat.
64	Flag Station Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted
65	Flight Charge Certificate Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted
66	Flying Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
67	Flying Squad Allowance	Abolished.	Accepted
68	Free Fall Jump Instructor Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
69	Funeral Allowance	Abolished	Retained with change in nomenclature as 'Funeral Expense'. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹6000 to ₹9000.
70	Ghat Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
71	Good Service/Good Conduct/Badge Pay	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted
72	Haircutting Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Composite Personal Maintenance Allowance.	Accepted
73	Handicapped Allowance	Abolished.	Accepted
74	Hard Area Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted
75	Hardlying Money	Retained. Rationalised. Full Rate to be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
76	Headquarters Allowance	Abolished.	Accepted
77	Health and Malaria Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
78	High Altitude Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
79	Higher Proficiency Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by Language Award or Higher Qualification Incentive for Civilians.	Accepted
80	Higher Qualification Incentive for Civilians	Retained. Rationalized.	Accepted
81	Holiday Compensatory Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by National Holiday Allowance	Not to be subsumed and retained as a separate allowance. Existing system to continue in Intelligence Bureau (IB) and Research and Analysis Wing (RAW).

(1)	(2)	(3)	(4)
82	Holiday Monetary Compensation	Retained. Rationalized.	Accepted
83	Hospital Patient Care Allowance (HPCA)/Patient Care Allowance (PCA)	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix. HPCA and PCA are admissible to ministerial staff as well on the premise that the entire hospital area carries the risk of communicable diseases. This practice should be stopped and HPCA/PCA should be admissible to only those employees who come in continuous and routine contact with the patients.	Ministerial Staff to continue to get HPCA/PCA as per R1H3 (₹4100 for level 8 and below and ₹5300 for level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix
84	House Rent Allowance (HRA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	The recommendations of the 7 th CPC is accepted with the following modifications: (i) HRA shall not be less than ₹5,400 per month, ₹3,600 per month and ₹1,800 per month calculated @30% of minimum pay for X (population of 50 lakh & above), 20% for Y (5 to 50 lakh) and 10% for Z (below 5 lakh) category of cities. (ii) HRA shall be revised to 27%, 18% and 9% of Basic Pay in X, Y and Z cities when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further to 30%, 20% and 10% of Basic Pay in X, Y and Z cities when DA crosses 50%.
85	Hutting Allowance	Abolished.	Accepted
86	Hydrographic Survey Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
87	Initial Equipment Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted
88	Instructional Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by Training Allowance.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
89	Internet Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
90	Investigation Allowance	Abolished.	Accepted
91	Island Special Duty Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted
92	Judge Advocate General Department Examination Award	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Higher Qualification Incentive for Defence Personnel.	Accepted
93	Kilometrage Allowance (KMA)	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.
94	Kit Maintenance Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Subsumed in Dress Allowance for Special Protection Group (SPG) and factored in for determining the revised rates of Dress Allowance for SPG.
95	Language Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
96	Language Award	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
97	Language Reward and Allowance	Abolished.	Accepted
98	Launch Campaign Allowance	Abolished.	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
99	Leave Travel Concession (LTC)	Retained. Rationalized. One additional free railway warrant should be extended to all personnel of Central Armed Police Force (CAPFs) and the Indian Coast Guard mutatis mutandis.	The recommendations of the 7th CPC on LTC are accepted without any change. However, keeping in view the fact that Indian Navy personnel are not deployed for Field Duties, additional free Railway Warrant to Indian Coast Guard shall not be granted.
100	Library Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
101	MARCOS and Chariot Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
102	Medal Allowance	Retained.	Accepted
103	Messing Allowance	Retained for "floating staff" under Fishery Survey of India, and enhanced by 50%. Abolished for Nursing Staff.	Accepted
104	Metropolitan Allowance	Abolished.	Accepted
105	Mileage Allowance for journeys by road	Retained.	Accepted
106	Mobile Phone Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
107	Monetary Allowance attached to Gallantry Awards	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
108	National Holiday Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
109	Newspaper Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
110	Night Duty Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
111	Night Patrolling Allowance	Abolished.	Accepted.
112	Non-Practicing Allowance (NPA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted
113	Nuclear Research Plant Support Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
114	Nursing Allowance	Retained. Rationalized.	Existing rates multiplied by 1.5. Rates revised from ₹4800 per month to ₹7200 per month.
115	Official Hospitality Grant in Defence forces	Abolished.	Accepted
116	Officiating Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
117	Operation Theatre Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹360 per month to ₹540 per month.

(1)	(2)	(3)	(4)
118	Orderly Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
119	Organization Special Pay	Abolished.	Accepted
120	Out of Pocket Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by Daily Allowance on Foreign Travel.	Accepted
121	Outfit Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted.
122	Outstation (Detention) Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.
123	Outstation (Relieving) Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.
124	Out-turn Allowance	Abolished.	Accepted
125	Overtime Allowance (OTA)	Abolished except for operational staff and industrial employees governed by statutory provisions.	Ministries/Departments to prepare a list of those staff coming under the category of 'operational staff'. Rates of Overtime Allowance not to be revised upwards.
126	Para Allowances	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
127	Para Jump Instructor Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
128	Parliament Assistant Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
129	PCO Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
130	Post Graduate Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
131	Professional Update Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories	This allowance to continue to be paid to non-gazetted staff of Department of Atomic Energy (DAE). Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.

(1)	(2)	(3)	(4)
132	Project Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
133	Qualification Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories.	Accepted
134	Qualification Grant	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Higher Qualification Incentive for Defence Personnel. Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel	7 th CPC recommendations accepted with the modifications that- (i) this will not include Tier – II courses, and (ii) courses will be reviewed by associating experts, including outside professionals and academicians by 31.12.2017.
135	Qualification Pay	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted
136	Rajbhasha Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed “Extra Work Allowance”	Accepted
137	Rajdhani Allowance	Abolished.	Accepted
138	Ration Money Allowance	Retained. Rationalized. Provision of free rations and the grant of Ration Money Allowance to officers of Defence forces posted in peace areas should be withdrawn	Provision of free ration for officers of Defence Forces shall be discontinued in peace areas. Ration Money Allowance shall continue to be paid to officers of Defence Forces posted in peace areas. The cash shall be credited directly into the bank accounts of officers.
139	Refreshment Allowance	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
140	Rent Free Accommodation	Abolished.	Accepted
141	Reward for Meritorious Service	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted
142	Risk Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 2.25. Rates revised from ₹60 per month to ₹135 per month.
143	Robe Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted
144	Robe Maintenance Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted
145	Savings Bank Allowance	Abolished.	Accepted
146	Sea Going Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
147	Secret Allowance	Abolished.	Accepted
148	Shoe Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted
149	Shorthand Allowance	Abolished.	Accepted
150	Shunting Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
151	Siachen Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Rates revised from: ₹31500 to ₹42500 per month for Level 9 and above, and ₹21000 per month to ₹30000 per month for level 8 and below

(1)	(2)	(3)	(4)
152	Single in Lieu of Quarters (SNLQ)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed provisions for Housing for PBORs.	Accepted
153	Soap Toilet Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Composite Personal Maintenance Allowance.	Accepted
154	Space Technology Allowance	Abolished.	Retained. Existing rate to be multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
155	Special Allowance for Child Care for Women with Disabilities	Retained. Enhanced by 100%.	Accepted
156	Special Allowance to Chief Safety Officers/Safety Officers	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted
157	Special Appointment Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance". Granted to CAPF Personnel holding special appointments	To include Assistant Sub Inspector (Radio Mechanic), Assistant Sub Inspector (Radio Operator) and Sub Inspector (Radio Mechanic) in the list eligible for Extra Work Allowance @2% of Basic Pay per month with the conditions recommended by the 7 th CPC.
158	Special Compensatory (Hill Area) Allowance	Abolished.	Accepted
159	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Tough Location Allowance (TLA) - I, II or III. Tough Location Allowance will not be admissible along with Special Duty Allowance.	7 th CPC recommendations that Tough Location Allowance (TLA) will not be admissible along with Special Duty Allowance (SDA) accepted subject to condition that employees be given the additional option to avail of the benefit of Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA) at pre-revised rates under the 6 th CPC regime along with SDA at revised rates of 7 th CPC

(1)	(2)	(3)	(4)
160	Special Department of Telecom (DOT) Pay	Abolished.	Accepted
161	Special Duty Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. SDA for AIS officers should be paid at the rate of 30 per cent of Basic Pay and for other civilian employees at the rate of 10 per cent of Basic Pay.	As per DoPT's OM No. 14017/4/2005-AIS (II) dated 10 th February, 2009, 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of All India Service (AIS) officers' is granted @25%. Special Duty Allowance (SDA) is granted @12.5%. Rationalized by a factor of 0.8. Both these allowances namely 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of AIS' and Special Duty Allowance (SDA) shall continue to be paid separately as at present at the revised rates of 20% and 10% respectively.
162	Special Forces Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
163	Special Incident/Investigation/Security Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Department of Revenue should assess the risk profile of the officials of the Enforcement Directorate (ED) at various levels and thereafter make a case to Ministry of Finance for grant of Risk and Hardship Allowance, if any, as per appropriate cell.	Special Security Allowance (SSA) for Special Protection Group (SPG) to be revised from 40% to 55% of Basic Pay for operational duties and from 20% to 27.5% of Basic Pay for non – operational duties. National Technical Research Organisation (NTRO) employees to be granted this allowance @20% of Basic Pay. This allowance was granted to Enforcement Directorate as an ad – hoc measure with the approval of Department of Expenditure pending recommendations of the 7 th CPC. Accordingly, this allowance to be withdrawn from ED with effect from 01.07.2017. As per recommendations of the 7 th CPC, D/o Revenue to examine proposal for Risk & Hardship allowance for ED to make a case to Ministry of Finance for granting Risk & Hardship based allowance to ED officials, if any.
164	Special Level Crossing (LC) Gate Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
165	Special National Crime Records Bureau (NCRB) Pay	Abolished.	Accepted
166	Special Running Staff Allowance	Retained. Extended to some more categories.	Name of the allowance to continue as 'Additional Allowance'.
167	Special Scientists' Pay	Abolished.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
168	Specialist Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
169	Spectacle Allowance	Abolished.	Accepted
170	Split Duty Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
171	Study Allowance	Abolished.	Accepted
172	Submarine Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
173	Submarine Duty Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix, on a pro-rata basis.	Accepted
174	Submarine Technical Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix. Extended to some more categories.	Accepted
175	Subsistence Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
176	Sumptuary Allowance in Training Establishments	Abolished.	Accepted
177	Sumptuary Allowance to Judicial Officers in Supreme Court Registry	Abolished.	Accepted
178	Sunderban Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Tough Location Allowance-III. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
179	TA Bounty	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Territorial Army Allowance.	Accepted
180	TA for Retiring Employees	Retained. Rationalized.	Accepted
181	TA on Transfer	Retained. Rationalized.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
182	Technical Allowance	<p>Tier-I of the Technical Allowance will continue to be paid on a monthly basis.</p> <p>Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel</p>	<p>Existing system of Technical Allowance (Tier – I and II) to continue at ₹3000 per month and ₹4500 per month up to 31.03.2018.</p> <p>Courses of Technical Allowance (Tier –I and II) along with Qualification Grant (Higher Qualification Incentive for Defence Personnel) to be reviewed by associating experts, outside professionals and academicians in order to keep pace with changing defence requirements.</p> <p>Review of Courses to be completed before 31.12.2017.</p> <p>Technical Allowance (Tier – II) to continue beyond 31.03.2018 only after review of courses.</p>
183	Tenure Allowance	Retained. Ceilings enhanced by 2.25.	Accepted
184	Test Pilot and Flight Test Engineer Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
185	Training Allowance	<p>Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Extended to some more categories.</p> <p>The allowance will be payable to an eligible employee for a maximum period of five years only during the entire career.</p>	<p>Ceiling of 5 years period to be removed.</p> <p>Standard cooling off period between tenures will apply.</p>
186	Training Stipend	Abolished.	Accepted
187	Transport Allowance (TPTA)	Retained. Rationalized.	Accepted.
188	Travelling Allowance	<p>Retained. Rationalized.</p> <p>Indian Railways to reconsider its position regarding air travel to its employees.</p>	<p>Level 6 to 8 of Pay Matrix to be entitled for Air travel.</p> <p>Level 5 A of Defence Forces to be clubbed with Level 6 for travelling entitlements.</p> <p>Existing system to continue in Ministry of Railways.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)									
189	Treasury Allowance	Abolished	Subsumed in Cash Handling and Treasury Allowance and rates revised as under: <div>(in ₹, per month)</div> <table><tr><th>Amount of average monthly cash handled</th><th>6th CPC rates</th><th>Revised Rates</th></tr><tr><td><= 5 lakh</td><td>230-600</td><td>700</td></tr><tr><td>Over 5 lakh</td><td>750-900</td><td>1000</td></tr></table>	Amount of average monthly cash handled	6 th CPC rates	Revised Rates	<= 5 lakh	230-600	700	Over 5 lakh	750-900	1000
Amount of average monthly cash handled	6 th CPC rates	Revised Rates										
<= 5 lakh	230-600	700										
Over 5 lakh	750-900	1000										
190	Tribal Area Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Tough Location Allowance-III. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted									
191	Trip Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.									
192	Uniform Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance and to be paid annually.	7 th CPC recommendations accepted with following modifications: Different rates for the following categories: (i) Special Protection Group (SPG) personnel- to be paid annually @ ₹27,800 per annum and ₹21,225 per annum for operational and non – operational duties respectively. (ii) Nurses – to be paid monthly @₹1800 per month To be extended to all Check Points of Bureau of Immigration.									
193	Unit Certificate and Charge Certificate Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted									
194	Vigilance Allowance	Abolished.	Accepted									
195	Waiting Duty Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance									
196	Washing Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Subsumed in Dress Allowance in respect of Nurses and factored in for determining the revised rates of Dress Allowance for Nurses.									

(1)	(2)	(3)	(4)
197	<p>New Allowances for Railways:</p> <p>(i) Special Train Controller's Allowance, and</p> <p>(ii) Risk and Hardship Allowance for Track Maintainers</p> <p>New Allowance for Fire-fighting Staff:</p> <p>(i) Risk and Hardship Allowance for Fire-fighting staff of Central Government & UTs</p>	<p>New Allowances for Railways:</p> <p>(i) Special Train Controller's Allowance -to be paid @₹5,000 per month to Section Controllers and Dy. Chief Controllers</p> <p>(ii) Track Maintainers – I, II, III and IV of Indian Railways to be granted Risk and Hardship Allowance as per cell R3H2 (₹2700 for Level 8 and below and ₹3400 for Level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix</p> <p>New Allowance for Fire-fighting Staff:</p> <p>(i) Risk and Hardship Allowance as per cell R2H3 (₹2700 for Level 8 and below and ₹3400 for Level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix</p>	Accepted

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.06 23:30:04 +05'30'

①

F. No. 1/1/2016-E-III(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 26th July, 2017

Office Memorandum

Subject: Revision of rates of Allowances -extension of Government decisions on the recommendations the 7th Central Pay Commission in respect of employees of Quasi-Government Organizations, Autonomous Organizations, Statutory Bodies set-up by and funded/controlled by the Central Government-regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Department's OM of even number dated 13.1.2017, regarding extension of revised pay scales based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission in respect of employees of Quasi-Government Organizations, Autonomous Organizations, Statutory Bodies set-up by and funded/controlled by the Central Government and to say that in terms of para 6 thereof, it was mentioned that the Central Government has not taken any decision in regard to various allowances based on the recommendation of the 7th Central Pay Commission in respect of Central Government employees and, therefore, until further orders, the existing allowances in the autonomous organizations shall continue to be admissible as per the existing terms and conditions, irrespective of the revised pay scales having been adopted.

2. The decision of the Central Government on the recommendations of the 7th Central Pay Commission in regard to allowances in respect of Central Government employees have since been announced as per this Department's Resolution No. 11-1/2016-IC dated 6.7.2017 and the consequent Government orders have also been issued by this Department in regard to allowances like HRA, Travelling Allowance, Transport Allowance, Family Planning Allowance, etc. The attention is also invited to this Department's OM No.29/1/2017-E-IIB dated 11th July, 2017 regarding non-disbursal of discontinued allowances.

3. Accordingly, it has been decided that such of the existing allowances at present admissible in case of employees of Quasi-Government Organizations, Autonomous Organizations, Statutory Bodies set-up by and funded/controlled by the Central Government, as are exactly as per the Central Government pattern, may be revised in accordance with the decision contained in the aforesaid Resolution dated 6.7.2017 read with the Government orders issued in the matter. The provisions contained in this Department's OM No. 29/1/2017-E-IIB dt. 11th July, 2017 regarding non-disbursal of discontinued allowances shall also be strictly followed.



4. All other stipulations including the modalities for additional financial impact on allowances, as contained in the OM dated 13.1.2017 referred to in para 1 above, shall continue to be applicable in regard to these orders.

5. Hindi version of these orders is attached.



(Amar Nath Singh)
Director

To

All Ministries/Departments of Government of India
All Financial Advisors of the Government of India.

New Delhi, 7th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Implementation of recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide that, in modification of this Ministry's O.M. No.2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 as amended from time to time, O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008 and O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, the admissibility of House Rent Allowance (HRA) shall be as under:-

Classification of Cities/Towns	Rate of House Rent Allowance per month as a percentage of Basic Pay only
X	24 %
Y	16 %
Z	8%

- The rates of HRA will not be less than Rs.5400/-, 3600/- & 1800/- at X, Y & Z class cities respectively.
- The rates of HRA will be revised to 27% 18% & 9% for X, Y & Z class cities respectively when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30%, 20% & 10% when DA crosses 50%.
- The term "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay levels in the Pay Matrix and does not include Non-Practising Allowance (NPA), Military Service Pay (MSP), etc. or any other type of pay like special pay, etc.
- The list of cities classified as 'X', 'Y' and 'Z' vide DoE's O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, for the purpose of grant of House Rent Allowance is enclosed as Annexure to these orders.
- Special orders on continuance of HRA at Delhi ("X" class city) rates to Central Government employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA and Gurgaon, at Jalandhar ("Y" class city) rates to Jalandhar Cantt., at "Y" class city rates to Shillong, Goa & Port Blair and HRA at par with Chandigarh ("Y" class city) to Panchkula, S.A.S. Nagar (Mohali) which have been allowed to continue vide Para '4' of this Ministry's O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015 and O.M. No. 2/2/2016-E.II(B) dated 03.02.2017, shall continue till further orders.
- All other conditions governing grant of HRA under existing orders, shall continue to apply.
- These orders shall be effective from 1st July, 2017.
- The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.
- In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is attached.

Annie George Mathew

(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to: C&AG and U.P.S.C., etc. as per standard endorsement list.

To O.M. No.2/5/2017-E.II(B) dated 07.07.2017.

**LIST OF CITIES/TOWNS CLASSIFIED FOR GRANT OF
HOUSE RENT ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	—	—
2.	ANDHRA PRADESH/ TELANGANA	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
3.	ARUNACHAL PRADESH	—	—
4.	ASSAM	---	Guwahati (UA)
5.	BIHAR	---	Patna (UA)
6.	CHANDIGARH	---	Chandigarh (UA)
7.	CHHATTISGARH	—	Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	—	—
9.	DAMAN & DIU	---	---
10.	DELHI	Delhi (UA)	---
11.	GOA	---	---
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA)
13.	HARYANA	---	Faridabad*(M.Corpn.), Gurgaon*(UA)
14.	HIMACHAL PRADESH	---	---
15.	JAMMU & KASHMIR	---	Srinagar (UA), Jammu (UA)
16.	JHARKHAND	—	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
17.	KARNATAKA	Bengalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
18.	KERALA	—	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvananthapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
19.	LAKSHADWEEP	---	---
20.	MADHYA PRADESH	—	Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M. Corpn.)

92

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
21.	MAHARASHTRA	Greater Mumbai (UA), Pune (UA)	Amravati (M.Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M.Corpn.), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M. Corpn.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M. Corpn.), Sangli (UA)
22.	MANIPUR	---	---
23.	MEGHALAYA	---	---
24.	MIZORAM	---	---
25.	NAGALAND	---	---
26.	ODISHA	---	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA)
27.	PUDUCHERRY (PONDICHERRY)	---	Puducherry/Pondicherry (UA)
28.	PUNJAB	---	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M. Corpn.)
29.	RAJASTHAN	---	Bikaner (M.Corpn.), Jaipur (M.Corpn.), Jodhpur (UA), Kota (M.Corpn.), Ajmer (UA)
30.	SIKKIM	---	---
31.	TAMIL NADU	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
32.	TRIPURA	---	---
33.	UTTAR PRADESH	---	Moradabad (M.Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad*(UA), Aligarh(UA), Agra (UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M.Corpn.), Noida* (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
34.	UTTARAKHAND	---	Dehradun (UA)
35.	WEST BENGAL	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

* Only for the purpose of extending HRA on the basis of dependency.

NOTE

The remaining cities/towns in various States/UTs which are not covered by classification as "X" or "Y", are classified as "Z" for the purpose of HRA.

83

F. No.12(4)/2016-EIII.A
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

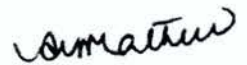
North Block, New Delhi
7th July, 2017

Office Memorandum

Subject: Discontinuance of Family Planning Allowance for adoption of small family norms-
recommendation of the 7th Central Pay Commission.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's OM No. 7(20)/2008-E-III.A dated 24.9.2008 regarding the existing rates of Family Planning Allowance (FPA) admissible to Central Government employees and to say that as provided for in para 7 of this Ministry's Resolution No. 1-2/2016-IC dated 25th July, 2016, the matter regarding allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission was referred to a Committee under the Chairmanship of Finance Secretary and until a final decision thereon, all allowances were required to be paid at the existing rates in the existing pay structure (the pay structure based on 6th Pay Commission) as if the pay has not been revised w.e.f. 1st January, 2016. Accordingly, FPA was also required to be paid at the existing rates specified in the aforesaid OM dated 24.9.2008.

2. The decisions of the Government on various allowances based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission and in the light of the recommendations of the Committee under the Chairmanship of the Finance Secretary, have since been notified as per the Resolution No. 11-1/2016-IC dated 6th July, 2017
3. As mentioned at Sl. No. 60 of the Appendix –II of the said Resolution dated 6th July, 2017, the recommendation of the 7th Central Pay Commission to abolish Family Planning Allowance has been accepted and this decision is effective from 1st July, 2017. Accordingly, FPA Family Planning Allowance, as admissible hitherto, shall cease to exist in all cases
4. These orders shall take effect from 1st July, 2017 and hence Family Planning Allowance shall stand discontinued w.e.f. 1st July, 2017.
5. In their application to the employees serving in the Indian Audit & Accounts Department, these orders are issued in consultation with the Office of C&AG.
6. Hindi version of these orders is attached.



(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

To,

All Ministries & Departments

54

New Delhi, dated the 7th July 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Implementation of the recommendations of the 7th Central Pay Commission relating to grant of Transport Allowance to Central Government employees.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President, is pleased to decide that Transport Allowance shall be admissible to Central Government employees at the following rates:-

Employees drawing pay in Pay Level	Rates of Transport Allowance per month	
	Employees posted in the Cities as per Annexure	Employees posted at all Other Places
9 and above	Rs. 7200 + DA thereon	Rs.3600+ DA thereon
3 to 8	Rs. 3600 + DA thereon	Rs.1800+ DA thereon
1 and 2	Rs.1350 + DA thereon	Rs.900 + DA thereon

2. The grant of Transport Allowance shall be subject to the following conditions:-

- (i) The allowance shall not be admissible to those employees who have been provided with the facility of Government transport.
- (ii) In respect of those employees who opt to continue in their pre-revised Pay-structure/Pay Scales, the corresponding Level in the Pay Matrix of the post occupied on 01.01.2016 as indicated in CCS (Revised Pay) Rules, 2016 would determine the allowance under these orders.
- (iii) Physically disabled employees as mentioned in DoE O.M. No. 19029/1/78-E.IV(B) dated 31.08.1978 and subsequent orders in respect of the categories viz. visually impaired, orthopaedically handicapped, deaf and dumb/hearing impaired, spinal deformity, shall continue to be paid Transport Allowance at double the normal rates, subject to fulfilment of the stipulated conditions, which shall, in no case, be less than Rs.2250/- p.m. plus applicable rates of Dearness Allowance
- (iv) Officers drawing pay in Levels 14 and above in the Pay Matrix, who are entitled to the use of official car in terms of Department of Expenditure's O.M. No.20(5)-E.II(A)/93 dated 28.01.1994, shall be given the option to avail the official car facility or to draw Transport Allowance at the rates of Rs.15,750/- p.m. plus Dearness Allowance thereon. Before, allowing Transport Allowance @ Rs.15,750/- plus D.A. thereon, the option exercised by an officer will be examined by the administrative Ministry and his/her entitlement to the use of official car in terms of the O.M. dated 28.01.1994 ibid will require to be certified by the competent authority. In case, an officer opts to draw Transport Allowance @ Rs.15,750/- p.m. plus D.A. thereon, he/she will not be allowed to change his/her option during the remaining period of his/her current assignment.

3. **Admissibility of Transport Allowance during the following circumstances:-**

- (a) **During leave:** The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.
- (b) **During deputation abroad:** The allowance will not be admissible during the period of deputation abroad.
- (c) **During tour:** If an employee is absent from the Headquarters/Place of Posting for full calendar month(s) due to tour, he/she will not be entitled to Transport Allowance during that/those calendar month/months. However, If the absence does not cover any calendar month(s) in full, Transport Allowance will be admissible for full month.
- (d) **During training treated as duty:** The allowance may be granted during such training, if no Transport Facility/Travelling Allowance/Daily Allowance is provided for attending the training institute. During official tour in the training course, the allowance will not be admissible when the period of the tour covers the whole calendar month. Also, during training abroad, no Transport Allowance will be admissible when the period of such training covers the whole calendar month.

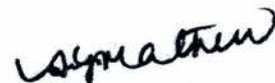
- (e) During inspection/survey duty by Members of Special Parties within the city but exceeding 8 kms. from the Headquarters OR during continuous field duty either in or outside the Headquarters: Transport Allowance is given to compensate for the expenditure incurred for commuting for both to and from between the place of duty and residence. In case when one gets Road Mileage/Daily Allowance or free transportation for field/inspection/survey duty or tour for a period covering the whole calendar month, he/she will not be entitled to Transport Allowance during that calendar month.
- (f) To vacation staff : Vacation staff is entitled to Transport Allowance provided no free transport facility is given to such staff. However, the allowance shall not be admissible when such vacation spell, including all kinds of leave, cover the whole calendar month(s).
- (g) During suspension: As a Government employee under suspension is not required to attend office, he/she is not entitled to Transport Allowance during suspension where suspension covers full calendar month(s). This position will hold good even if the suspension period is finally treated as duty. Where suspension period covers a calendar month partially, Transport Allowance payable for that month shall be reduced proportionately.

4. These orders shall be effective from 1st July, 2017.

5. These orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also apply to the civilian employees paid from the Defence Service Estimates. In respect of the Armed Forces Personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is attached.



(Annie George Mathew)

Joint Secretary to the Government of India.

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. as per standard endorsement list.

LIST OF CITIES/TOWNS ELIGIBLE FOR HIGHER RATES OF TRANSPORT ALLOWANCE ON RE-CLASSIFICATION OF CITIES/TOWNS AS PER CENSUS-2011 (w.e.f 01.04.2015)

S. No.	NAME OF THE STATES/ UNION TERRITORIES	NAME OF THE CITY/TOWN
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	---
2.	ANDHRA PRADESH/ TELANGANA	Hyderabad (UA)
3.	ARUNACHAL PRADESH	---
4.	ASSAM	---
5.	BIHAR	Patna (UA)
6.	CHANDIGARH	---
7.	CHHATTISGARH	---
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	---
9.	DAMAN & DIU	---
10.	DELHI	Delhi (UA)
11.	GOA	---
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA), Surat (UA)
13.	HARYANA	---
14.	HIMACHAL PRADESH	---
15.	JAMMU & KASHMIR	---
16.	JHARKHAND	---
17.	KARNATAKA	Bengalore / Bengaluru (UA)
18.	KERALA	Kochi (UA), Kozhikode (UA)
19.	LAKSHADWEEP	---
20.	MADHYA PRADESH	Indore (UA)
21.	MAHARASHTRA	Greater Mumbai (UA); Nagpur (UA); Pune (UA)
22.	MANIPUR	---
23.	MEGHALAYA	---
24.	MIZORAM	---
25.	NAGALAND	---
26.	ODISHA	---
27.	PUDUCHERRY/ PONDICHERRY	---
28.	PUNJAB	---
29.	RAJASTHAN	Jaipur (UA)
30.	SIKKIM	---
31.	TAMIL NADU	Chennai (UA), Coimbatore (UA)
32.	TRIPURA	---
33.	UTTAR PRADESH	Ghaziabad (UA), Kanpur (UA), Lucknow (UA)
34.	UTTARAKHAND	---
35.	WEST BENGAL	Kolkata(UA)

83

F.No.29/1/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, dated the 11th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Payment on account of discontinued allowances – regarding.

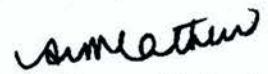
The undersigned is directed to inform that the recommendations of the 7th CPC on allowances have been accepted by the Government with 34 modifications. Resolution in this regard has been published on 6th July, 2017.

2. In this regard, attention is drawn to Para 8.2.5 of the Report of the 7th CPC wherein it has been mentioned that any allowance, not mentioned in the Report (and hence not reported to the Commission), shall cease to exist immediately. In case there is any demand or requirement for continuation of an existing allowance which has not been deliberated upon or covered in this report, it should be re-notified by the Ministry concerned after obtaining due approval of Ministry of Finance and should be put in the public domain.

3. As the recommendations of the 7th CPC on allowances have come into effect from 1st July, 2017, disbursement of all existing allowances which have not been specifically recommended for continuation in terms of the Resolution dated 6th July, 2017 shall be discontinued from the salary of the month of July, 2017.

4. In view of the nature of the Allowances specific to Ministry of External Affairs, these allowances were not covered by the 7th Central Pay Commission. Hence this order will not be applicable to allowances specific to Ministry of External Affairs.

5. It shall be the responsibility of the Heads of the Department to ensure that no bills relating to disbursement in respect of such allowances is drawn by the Head of Office/Drawing & Disbursing Officers under their purview/jurisdiction. Pay and Accounts Officers shall ensure that no payment is effected if any such bill relating to the disbursement of the discontinued allowances is submitted to them. If such bills are received, they should be returned to the DDO and intimation thereof shall also be given to the Head of the Department and the Chief Controller of Accounts.


(Annie George Mathew)

Joint Secretary to the Government of India

To

1. Joint Secretary(Admn./Estt.), all Ministries/Departments
2. All Financial Advisors

83

No. 4/1/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 13th July, 2017.


OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Abolition of Special Compensatory(Hill Area) Allowance - Recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide that, **Special Compensatory (Hill Area) Allowance stands abolished with effect from 1st July, 2017.** This allowance was admissible to Central Government employees vide this Ministry's O.M. No. 4(2)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008.

2. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
3. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

Hindi version is attached.


(Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

New Delhi, the 13th July 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Travelling Allowance Rules - Implementation of the Seventh Central Pay Commission.

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Travelling Allowance entitlements to civilian employees of Central Government, President is pleased to decide the revision in the rates of Travelling Allowance as set out in the Annexure to this Office Memorandum.

2. The 'Pay Level' for determining the TA/DA entitlement is as indicated in Central Civil Service (Revised Pay) Rules 2016.
3. The term 'Pay in the Level' for the purpose of these orders refer to Basic Pay drawn in appropriate Pay level in the Pay Matrix as defined in Rule 3(8) of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 and does not include Non-Practising Allowance (NPA), Military Service Pay (MSP) or any other type of pay like special pay, etc
4. However, if the Travelling Allowance entitlements in terms of the revised entitlements now prescribed result in a lowering of the existing entitlements in the case of any individual, groups or classes of employees, the entitlements, particularly in respect of mode of travel, class of accommodation, etc., shall not be lowered. They will instead continue to be governed by the earlier orders on the subject till such time as they become eligible, in the normal course, for the higher entitlements.
5. The claims submitted in respect of journey made on or after 1st July, 2017, may be regulated in accordance with these orders. In respect of journeys performed prior to 1st July, 2017, the claims may be regulated in accordance with the previous orders dated 23.09.2008.
6. It may be noted that no additional funds will be provided on account of revision in TA/DA entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements.
7. **These orders shall take effect from 01st July, 2017**
8. Separate orders will be issued by Ministry of Defence and Ministry of Railways in respect of Armed Forces personnel and Railway employees, respectively.
9. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India

Hindi version is attached.



(Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to: C&AG and U.P.S.C., etc. as per standard endorsement list.

1

ANNEXURE

**Annexure to Ministry of Finance, Department of Expenditure
O.M.No.19030/1/2017-E.IV dated 10th July 2017.**

In supersession of Department of Expenditure's O.M. No. 19030/3/2008-E.IV dated 23.09.2008, in respect of Travelling Allowance the following provisions will be applicable with effect from 01.07.2017 :

2. Entitlements for Journeys on Tour or Training

A.(i) Travel Entitlements within the Country

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
14 and above	Business/Club class by air or AC-I by train
12 and 13	Economy class by air or AC-I by train
6 to 11	Economy class by air or AC-II by train
5 and below	First Class/AC-III/AC Chair car by train

(ii) It has also been decided to allow the Government officials to travel by Premium Trains/Premium Tatkal Trains/Suvidha Trains, the reimbursement to Premium Tatkal Charges for booking of tickets and the reimbursement of Dynamic/Flexi-fare in Shatabdi/Rajdhani/Duronto Trains while on official tour/ training. Reimbursement of Tatkal Seva Charges which has fixed fare, will remain continue to be allowed. Travel entitlement for the journey in Premium/Premium Tatkal/Suvidha/ Shatabdi/Rajdhani/ Duronto Trains will be as under :-

Pay Level in Pay matrix	Travel Entitlements in Premium/Premium Tatkal/Suvidha/ Shatabdi/ Rajdhani/ Duronto Trains
12 and above	Executive/AC 1 st Class (In case of Premium/Premium Tatkal/Suvidha/Shatabdi/Rajdhani Trains as per available highest class)
6 to 11	AC 2 nd Class/Chair Car (In Shatabdi Trains)
5 & below	AC 3 rd Class/Chair Car

(iii) The revised Travel entitlements are subject to following:-

- In case of places not connected by rail, travel by AC bus for all those entitled to travel by AC II Tier and above by train and by Deluxe/ordinary bus for others is allowed.
- In case of road travel between places connected by rail, travel by any means of public transport is allowed provided the total fare does not exceed the train fare by the entitled class.
- All mileage points earned by Government employees on tickets purchased for official travel shall be utilized by the concerned department for other official travel by their officers. Any usage of these mileage points for purposes of private travel by an officer will attract departmental action. This is to ensure that the benefits out of official travel, which is funded by the Government, should accrue to the Government.
- In case of non-availability of seats in entitled class, Govt. servants may travel in the class below their entitled class.

B. International Travel Entitlement :

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
17 and above	First class
14 to 16	Business/Club class
13 and below	Economy class

C. Entitlement for journeys by Sea or by River Steamer

(i) For places other than A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of Island :-

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
9 and above	Highest class
6 to 8	Lower class if there be two classes only on the steamer
4 and 5	If two classes only, the lower class. If three classes, the middle or second class. If there be four classes, the third class
3 and below	Lowest class

(ii) For travel between the mainland and the A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of Island by ships operated by the Shipping Corporation of India Limited :-

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
9 and above	Deluxe class
6 to 8	First/ 'A' Cabin class
4 and 5	Second/ 'B' Cabin class
3 and below	Bunk class

D. Mileage Allowance for Journeys by Road :

(i) At places where specific rates have been prescribed :-

Pay Level in Pay Matrix	Entitlements
14 or above	Actual fare by any type of public bus including AC bus OR At prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC taxi OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped, etc.
6 to 13	Same as above with the exception that journeys by AC taxi will not be permissible.
4 and 5	Actual fare by any type of public bus other than AC bus OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped, etc.
3 and below	Actual fare by ordinary public bus only OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by autorickshaw, own scooter, motor cycle, moped, etc.

(ii) At places where no specific rates have been prescribed either by the Directorate of Transport of the concerned State or of the neighboring States:

For journeys performed in own car/taxi	Rs. 24/- per Km
For journeys performed by auto rickshaw , own scooter, etc	Rs. 12/- per Km

At places where no specific rates have been prescribed, the rate per km will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent.

E(i). Daily Allowance on Tour

Pay level in pay matrix	Entitlement
14 and above	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹7,500/- per day, Reimbursement of AC taxi charges as per actual expenditure commensurate with official engagements for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding ₹1200/- per day.
12 and 13	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹4,500/- per day, Reimbursement of AC taxi charges of up to 50 km per day for travel within the city, Reimbursement of food bills not exceeding ₹1000/- per day.
9 to 11	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹2,250/- per day, Reimbursement of non-AC taxi charges of up to ₹338/- per day for travel within the city, Reimbursement of food bills not exceeding ₹900/- per day.
6 to 8	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹750 per day, Reimbursement of non-AC taxi charges of up to ₹225/- per day for travel within the city, Reimbursement of food bills not exceeding ₹800/- per day.
5 and below	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹450 per day, Reimbursement of non-AC taxi charges of up to ₹113/- per day for travel within the city, Reimbursement of food bills not exceeding ₹500/- per day.

(ii) **Reimbursement of Hotel charges** :- For levels 8 and below, the amount of claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of stay, name of dwelling, etc. Additionally, for stay in Class 'X' cities, the ceiling for all employees up to Level 8 would be ₹1,000 per day, but it will only be in the form of reimbursement upon production of relevant vouchers. The ceiling for reimbursement of hotel charges will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent

(iii) **Reimbursement of Travelling charges** :- Similar to Reimbursement of staying accommodation charges, for levels 8 and below, the claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of travel, vehicle number, etc. The ceiling for levels 11 and below will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. For journeys on foot, an allowance of Rs.12/- per kilometer travelled on foot shall be payable additionally. This rate will further increase by 25% whenever DA increases by 50%.

(iv) **Reimbursement of Food charges** :- There will be no separate reimbursement of food bills. Instead, the lump sum amount payable will be as per Table E(i) above and, depending on the length of absence from headquarters, would be regulated as per Table (v) below. Since the concept of reimbursement has been done away with, no vouchers will be required. This methodology is in line with that followed by Indian Railways at present (with suitable enhancement of rates). i.e. Lump sum amount payable. The lump sum amount will increase by 25 percent whenever DA increase by 50 percent.

(v) Timing restrictions

Length of absence	Amount Payable
If absence from headquarters is <6 hours	30% of Lump sum amount
If absence from headquarters is between 6-12 hours	70% of Lump sum amount
If absence from headquarters is >12 hours	100% of Lump sum amount

Absence from Head Quarter will be reckoned from midnight to midnight and will be calculated on a per day basis.

(vi) In case of stay/journey on Government ships, boats etc. or journey to remote places on foot/mules etc for scientific/data collection purposes in organization like FSI, Survey of India, GSI etc., daily allowance will be paid at rate equivalent to that provided for reimbursement of food bill. However, in this case, the amount will be sanctioned irrespective of the actual expenditure incurred on this account with the approval of the Head of Department/controlling officer.

Note : DA rates for foreign travel will be regulated as prescribed by Ministry of External Affairs.

3. T.A. on Transfer

TA on Transfer includes 4 components : - (i) Travel entitlement for self and family (ii) Composite Transfer and packing grant (CTG) (iii) Reimbursement of charges on transportation of personal effects (iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

(i) Travel Entitlements :

- (a) Travel entitlements as prescribed for tour in Para 2 above, except for International Travel, will be applicable in case of journeys on transfer. The general conditions of admissibility prescribed in S.R.114 will, however, continue to be applicable.
- (b) The provisions relating to small family norms as contained in para 4(A) of Annexure to M/o Finance O.M. F.No. 10/2/98-IC & F.No. 19030/2/97-EIV dt. 171, April 1998, shall continue to be applicable.

(ii) Composite Transfer and Packing Grant (CTG) :

- (a) The Composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of the last month's basic pay in case of transfer involving a change of station located at a distance of or more than 20 kms from each other. However, for transfer to and from the Island territories of Andaman, Nicobar & Lakshadweep, CTG shall be paid at the rate of 100% of last month's basic pay. Further, NPA and MSP shall not be included as part of basic pay while determining entitlement for CTG.
- (b) In cases of transfer to stations which are at a distance of less than 20 kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.
- (c) In cases where the transfer of husband and wife takes place within six months, but after 60 days of the transfer of the spouse, fifty percent of the transfer grant on transfer shall be allowed to the spouse transferred later. No transfer grant shall be admissible to the spouse transferred later, in case both the transfers are ordered within 60 days. The existing provisions shall continue to be applicable in case of transfers after a period of six months or more. Other rules precluding transfer grant in case of transfer at own request or transfer other than in public interest, shall continue to apply unchanged in their case.

(iii) Transportation of Personal Effects

Level	By Train/Steamer	By Road
12 and above	6000 Kg by goods train/4 wheeler wagon/ 1 double container	Rs. 50/- per km
6 to 11	6000 Kg by goods train/4 wheeler wagon/ 1 single container	Rs. 50/- per km
5	3000 kg	Rs. 25/- per km
4 and below	1500 kg	Rs. 15/- per km

The rates will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. The rates for transporting the entitled weight by Steamer will be equal to the prevailing rates prescribed by such transport in ships operated by Shipping Corporation of India. The claim for reimbursement shall be admissible subject to the production of actual receipts/ vouchers by the Govt. servant. Production of receipts/vouchers is mandatory in r/o transfer cases of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep also.

Transportation of personal effects by road is as per kilometer basis only. The classification of cities /towns for the purpose of transportation of personal effects is done away with.

(iv) **Transportation of Conveyance.**

Level	Reimbursement
6 and above	1 motor car etc. or 1 motor cycle/scooter
5 and below	1 motorcycle/scooter/moped/bicycle

The general conditions of admissibility of TA on Transfer as prescribed in S.R. 116 will, however, continue to be applicable.

4 T.A. Entitlement of Retiring Employees

TA on Retirement includes 4 components : - (i) Travel entitlement for self and family (ii) Composite Transfer and packing grant (CTG) (iii) Reimbursement of charges on transportation of personal effects (iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

(i) **Travel Entitlements**

Travel entitlements as prescribed for tour/transfer in Para 2 above, except for International Travel, will be applicable in case of journeys on retirement. The general conditions of admissibility prescribed in S.R.147 will, however, continue to be applicable.

(ii) **Composite Transfer Grant(CTG)**

- (a) The Composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of the last month's basic pay in case of those employees, who on retirement, settled down at places other than last station(s) of their duty located at a distance of or more than 20 km. However, in case of settlement to and from the Island territories of Andaman, Nicobar & Lakshadweep, CTG shall be paid at the rate of 100% of last month's basic pay. Further, NPA and MSP shall not be included as part of basic pay while determining entitlement for CTG. The transfer incidentals and road mileage for journeys between the residence and the railway station/bus stand, etc., at the old and new station, are already subsumed in the composite transfer grant and will not be separately admissible.
- (b) As in the case of serving employees, Government servants who, on retirement, settle at the last station of duty itself or within a distance of less than 20 kms may be paid one third of the CTG subject to the condition that a change of residence is actually involved.

(iii) **Transportation of Personal Effects :-** Same as Para 3(iii) above.

(iv) **Transportation of Conveyance :-** Same as Para 3(iv) above.

The general conditions of admissibility of TA on Retirement as prescribed in S.R. 147 will, however, continue to be applicable.

95

No.11/1/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 18th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of the recommendations of the 7th Central Pay Commission - Grant of Special Duty Allowance for the Central Government employees serving in the North Eastern Region and Ladakh.

Consequent upon the acceptance of the recommendations of Seventh Central Pay Commission by the Government, the President, in supersession of all existing orders issued on the subject from time to time, is pleased to decide that Central Government employees, serving in the North Eastern Region and Ladakh, shall be paid Special Duty Allowance (SDA) at the rate of 10% of Basic Pay.

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Levels in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.

3. Special Duty Allowance will not be admissible along with Tough Location Allowance. Employees will have the additional option to avail of the benefit of Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA) as per 6th Central Pay Commission rates along with Special Duty Allowance at revised rates.

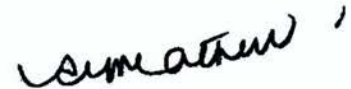
4. Special Duty Allowance shall not be admissible during the periods of leave/training/tour etc. beyond full calendar month(s), in case, the employee is outside the North-Eastern Region and Ladakh during leave/training/tour etc. The allowance shall not be admissible during suspension and joining time.

5. These orders shall take effect from 1st July, 2017.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

Hindi version is attached.



(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

96

No. 28/1/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 19th July, 2017.

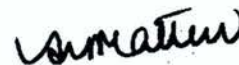
OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission – Additional HRA for civilian employees of the Central Government serving in the States of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and Ladakh.

Consequent upon revision of the rates of HRA granted to the Central Government employees on implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission vide O.M. No. 2/5/2017-E.II(B) dated 07.07.2017, in modification of this Ministry's O.M. No. 11016/1/E.II(B)/84 dated 29.03.1984 and O.M. No. 2(19)/E.II(B)/2008 dated 02.01.2009 on the subject mentioned above, additional HRA shall be granted to the civilian employees of the Central Government posted to States of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and Ladakh, who leave their families behind at their old duty station at revised rates as per O.M. No. 2/5/2017-E.II(B) dated 07.07.2017.

2. These orders, will not be applicable to such employees who were transferred out of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Islands and Ladakh before 1.7.2017.
3. These orders shall take effect from 1st July, 2017.
4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
5. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

Hindi version is attached.



(Annie George Mathew)

Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list

(97)

F.No. 19039/03/2017-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 19th July, 2017

OFFICE MEMEORANDUM

Subject : Implementation of the recommendation of the Seventh Central Pay Commission- Conveyance Allowance.

Consequent upon the acceptance of the recommendation of the Seventh Central Pay Commission and in supersession of this Department OM No. 19039/2/2008-E.IV, dated 23rd September, 2008 the President is pleased to revise the rates of Fixed Conveyance Allowance admissible under SR-25 to Central Government employees as indicated below:

Average Monthly Travel on Official Duty	(Rs. per month)	
	For Journey by Own Motor Car	For Journeys by other Modes of Conveyance
201-300 km	1680	556
301-450 km	2520	720
451-600 km	2980	960
601-800 km	3646	1126
>800 km	4500	1276

2. These rates shall automatically increase by 25% whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.
3. Conditions and provisions mentioned in SR 25 shall continue to apply
4. These orders will be effective from 1st July, 2017.
5. In so far as the staff serving in the Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is attached.

Annie George Mathew

(Annie George Mathew)

Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

C&AG and UPSC etc. (as per standard endorsement list).

No.3/1/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 19th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission - Grant of Special Compensatory Allowances subsumed under Tough Location Allowance.

Consequent upon the acceptance of the recommendations of Seventh Central Pay Commission, in supersession of the existing orders for grant of Special Compensatory Allowances viz. Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Bad Climate Allowance, Special Compensatory Scheduled/Tribal Area Allowance and Sunderban Allowance which have been subsumed in Tough Location Allowance, the President is pleased to decide the rates of these Special Compensatory Allowances (subsumed in Tough Location Allowance) to Central Government employees as under:-

Sl.No.	Name of the Allowance	Category	Cell Name	Pay Level in Pay Matrix	Rate per month (in Rs.)
(I)	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance: (i) Special Compensatory (Remote Locality) Allowance Places covered under Part-A & B (Annexure I & II)	Tough Location Allowance-I	R3H1	Level 9 and above	5,300
				Level 8 and below	4,100
		Tough Location Allowance-II	R3H2	Level 9 and above	3,400
				Level 8 and below	2,700
		Tough Location Allowance-III	R3H3	Level 9 and above	1,200
				Level 8 and below	1,000
(II)	Bad Climate Allowance	Tough Location Allowance-III	R3H3	Level 9 and above	1,200
				Level 8 and below	1,000
(III)	Tribal Area Allowance	Tough Location Allowance-III	R3H3	Level 9 and above	1,200
				Level 8 and below	1,000
(IV)	Sunderban Allowance	Tough Location Allowance-III	R3H3	Level 9 and above	1,200
				Level 8 and below	1,000

2. These rates shall increase by 25 per cent whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50 per cent.

3. The term 'Pay Level' in the revised pay structure means the 'Level in the Pay Matrix.

Contd..2/-

4. In respect of those employees who opt to continue in their pre-revised pay structure/Pay scales, the corresponding Level in the Pay Matrix of the post occupied on 01.01.2016 as indicated in CCS (Revised Pay) Rules, 2016 would determine the allowance under these orders.

5. Sunderban Allowance categorised as Tough Location Allowance-III shall be admissible to the Central Government civilian employees working in Sunderban areas South of Dampier Hodge's line, namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Paratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghusighata (Kulti) area. The allowance shall be admissible only upto the period for which the Government of West Bengal continues to pay this allowance to its employees.

6. Scheduled/Tribal Area Allowance and Bad Climate Allowance categorised as Tough Location Allowance-III shall be admissible only in those States where Scheduled/Tribal Area Allowance and Bad Climate Allowance are admissible and shall be discontinued in those States where it has been discontinued for the State Government employees with effect from the date(s) of such discontinuance.

7. In the event of a place falling in more than one category, the higher rate of Tough Location Allowance will be applicable.

8. Tough Location Allowances shall not be admissible along with Special Duty Allowance. However, employees have the option for continuing Special Compensatory (Remote Locality) Allowance at old rates of 6th CPC, where it was admissible, along with Special Duty Allowance at revised rate of 10% of Basic Pay.

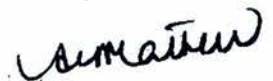
9. Employees may exercise their option to choose either Hard Area Allowance which is admissible along with Island Special Duty Allowance or one of the Special Compensatory Allowance, subsumed under Tough Location Allowance as mentioned in Para 1 above.

10. These orders take effect from 1st July, 2017.

11. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

12. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

Hindi version is attached.



(Annie George Mathew)

Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

ANNEXURE-I

ANNEXURE TO DEPARTMENT OF EXPENDITURE
O.M. NO. 3/1/2017-E.II(B) DATED 19th JULY, 2017

AREAS ELIGIBLE FOR GRANT OF SPECIAL COMPENSATORY (REMOTE LOCALITY) ALLOWANCE
SUBSUMED IN TOUGH LOCATION ALLOWANCE -I.

AREAS INCLUDED IN PART 'A'

S.No.	Name of States	Areas covered
1.	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	Middle Andamans, North Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands.
2.	ARUNACHAL PRADESH	Difficult Areas of Arunachal Pradesh
3.	HIMACHAL PRADESH	<p>1. Chamba District</p> <p>(a) Pangi Tehsil</p> <p>(b) Following Panchayats and Villages of Bharmour Tehsil:</p> <p>(i) Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda</p> <p>(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata.</p> <p>(2) Kinnaur District</p> <p>(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats.</p> <p>(b) 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi.</p> <p>(c) Pooh sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.</p> <p>(3) Kullu District</p> <p>15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga</p> <p>4) Lahaul and Spiti District } Entire area of Lahaul and Spiti</p> <p>5) Shimla District</p> <p>15/20 Area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda.</p>

:: 2 ::

4.	JAMMU & KASHMIR	1. Kathua District Niabat Bani, Lohi, Malhar and Macchodi.
		2. Udhampur District (a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote. (b) All Areas in Mahore Tehsil other than those included in Part 'B'.
		3. Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil.
		4. Leh District (a) Noyama and Nobre. (b) Zaskar (c) All other places in the District.
		5. Baramulla District Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa
5.	LAKSHADWEEP	Entire Union Territory.
6.	MIZORAM	Chimpuipui District and Areas beyond 25 km from Lunglei Town in Lunglei District.
7.	SIKKIM	Entire State.
8.	UTTARAKHAND	Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.

:: 3 ::

ANNEXURE-II

AREAS ELIGIBLE FOR GRANT OF SPECIAL COMPENSATORY (REMOTE LOCALITY) ALLOWANCE
SUBSUMED IN TOUGH LOCATION ALLOWANCE -I.

AREAS INCLUDED IN PART 'B'

<u>S.No.</u>	<u>Name of the States</u>	<u>Areas covered</u>
1	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	South Andaman (Including Port Blair)
2,	ARUNACHAL PRADESH	Throughout Arunachal Pradesh other than those declared as Difficult Areas.
3,	HIMACHAL PRADESH	<p>1. Chamba District Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 'A'.</p> <p>2. Kangra District Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal.</p> <p>3. Kinnaur District Entire District other than Areas included in Part 'A'</p> <p>4. Shimla District (a) Dodra-Kawar Tehsil. (b) Gram Panchayats of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish. (c) Ghorl Chaibis of Pargana Sarahan.</p>
4,	JAMMU & KASHMIR	<p>1. Udhampur District Areas up to Goel from Kamban side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mahore</p> <p>2. Baramulla District Matchill</p>
5.	MIZORAM	Entire Lunglei District excluding Areas beyond 25 km from Lunglei Town
6.	NAGALAND	Entire State.
7.	TRIPURA	Difficult Areas of Tripura.

103

:: 4 ::

ANNEXURE-III

**AREAS ELIGIBLE FOR GRANT OF SPECIAL COMPENSATORY (REMOTE LOCALITY) ALLOWANCE
SUBSUMED IN TOUGH LOCATION ALLOWANCE -II.**

AREAS INCLUDED IN PART 'C'

4.	HIMACHAL PRADESH	<p>1. Chamba District</p> <p>(a) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil.</p> <p>(b) Churah Tehsil</p> <p>(c) Dalhousie Town (including Banikhet proper)</p> <p>2. Kullu District</p> <p>(a) Outer Seraj (excluding Villages of Jakat-Khana and Burow in Nirmand Tehsil).</p> <p>(b) Entire District (excluding outer Seraj area and Pargana of Pandrabis but including villages Jakat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)</p> <p>3. Mandi District</p> <p>(a) Chhuhar Valley (Jogindernagar Tehsil).</p> <p>(b) Following Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chhatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Gharyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Samachan, Thachdhar, Tachi and Thana.</p> <p>(c) Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah.</p> <p>(d) Following Panchayats of Karsog Tehsil: Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban.</p> <p>(e) Following Panchayats of Sundernagar Tehsil: Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p>
----	------------------	---

:: 5 ::

		<p>4. Kangra District</p> <p>(I) Dharamsala Town and the following offices located outside its Municipal limits but included in Dharamsala Town for purposes of eligibility to Special Compensatory [Remote Locality]</p> <p>Allowance:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Women's ITI, Dari. (b) Mechanical Workshop, Ramnagar. (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh. (d) CRSF Office at lower Sakoh. (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar. (f) H.R.T.C. Workshop, Sudher. (g) Zonal Malaria Office, Dari. (h) Forest Corporation Office, Shamnagar. (i) Tea Factory, Dari. (j) I.P.H. Sub-Division, Dari. (k) Settlement Office, Shamnagar. (l) Binwa Project, Shamnagar. <p>(II) <u>Palampur Town</u>, including HPKVW Campus at Palampur and the following offices located outside its Municipal limits but included in Palampur Town for this purpose:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) H.P. Krishi Vishwavidhyalaya campus. (b) Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri. (c) Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla. (d) Electrical Sub-Division, Lohna. (e) D.P.O. Corporation, Bundla. (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar.
--	--	---

:: 6 ::

		5. Shimla District (I) (a) Chopal Tehsil. (b) (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan. (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area. (iii) Pargana Barabis. (iv) Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil. (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)
		6. Sirmaur District a) Following Panchayats: (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil) (ii) Bharog, Bhenieri (Paonta Tehsil) (iii) Birla (Nahan Tehsil) (iv) Dibber (Pachhad Tehsil) (v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil) (b) Thansgiri Tract
		Solan District Mangal Panchayat
2.	JAMMU & KASHMIR	(a) Areas in Poonch and Rajouri Districts excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other Urban areas in the two Districts. (b) Areas not included in Parts 'A', 'B' and (a) of Part 'C' above, but which are within a distance of 8 km from the line of actual control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.
3.	MANIPUR	Entire State.) ✓
4.	MIZORAM	Entire Aizwal District. 8
5.	TRIPURA	Entire State other than areas declared as Difficult ones and Included in Part 'B'.

::7::

ANNEXURE-IV**AREAS ELIGIBLE FOR GRANT OF SPECIAL COMPENSATORY (REMOTE LOCALITY) ALLOWANCE
SUBSUMED IN TOUGH LOCATION ALLOWANCE -III****AREAS INCLUDED IN PART 'D'**

1.	ASSAM	Entire State /
2.	HIMACHAL PRADESH	The remaining Areas of Himachal Pradesh not included in any of the Parts 'A', 'B' and 'C'.
3.	MEGHALAYA	Entire State.